Another small thing that I can share with you is that I have slight cervical problem. Sometimes when I move suddenly from this side to that side, it gives me trouble. So sometimes I will be asking the Deputy Chairman to preside over the House and sometimes the Vice-Chairman from the Panel. As and when it is necessary, I will be coming to the House. This is something personal. Please try to understand this and cooperate. Yesterday, Shri Swapan Dasgupta was speaking. He has got one more minute. Now, Shri Swapan Dasgupta.

#### \*DISCUSSION ON THE STATEMENT MADE BY MINISTER

### Regarding COVID-19 Pandemic and the Steps Taken by Government of India

SHRI SWAPAN DASGUPTA: Sir, I just wanted to resume whatever I was saying.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

Sir, the second issue which I wanted to emphasise was that while the Health Minister has spoken at length about the medical measures which have been taken to fight Covid-19, there has been relatively a greater degree of silence over the administrative measures which have been taken. We know that the 18-day or the 21-day lockdown which happened followed a certain pattern which began in Wuhan and then moved on to northern Italy, and it was to cut off infection by minimizing people's contact.

Sir, subsequently, when we entered the unlockdown phases, various States had undertaken their own localized lockdowns, ranging from two weeks to three weeks. Now, what I wanted to get from the Health Minister or from any other responsible Minister of the Government is what exactly the science or the thinking behind this is. All over the world, different practices are being adopted. We have heard about something called the Swedish model which basically says that there be no lockdown, more or less normal contact which exists among people, etc. Certain States have had localized lockdown; certain States have had random measures as if playing hide and seek with Covid situation or a game of Russian roulette. One day, something is put in; another day, another thing is put in and the people are inconvenienced in more ways than one. What I really wanted to stress is this. Is there a guideline, a national guideline, which, keeping the norms of federalism intact, can be followed so that the people really know and the administration knows what exactly they have to do? I think there is some confusion on this. Thank you very much for allowing me to complete.

<sup>\*</sup>Further Discussion continued from 16th Sept. 2020.

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर हम आज डिबेट कर रहे हैं। कल किसी ने यहां पर ठीक कहा कि हमने और हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार की महामारी आएगी और इतना बड़ा संकट आएगा, ऐसा सोचा नहीं था। कोविड-19 संक्रमण की चिंता पूरे विश्व में है, लेकिन जिसके घर में, जिसके परिवार में इस कोविड-19 का हमला हुआ है, उसका प्रेशर क्या होता है, उसके बारे में कल जया जी ने यहां बताया। जया जी, इसको में भी महसूस कर रहा हूं। मेरी माँ, जिनकी उम्र 80 साल की है, वे भी कोरोना से संक्रमित हैं और वे 15 दिन से अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। मेरा जो छोटा भाई है, जो महाराष्ट्र विधान सभा का विधायक है, वह भी कोरोना संक्रमित है। वह भी आईसीयू में भर्ती है। यह मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि कल वहां से हमारे साथी, वहां बैठकर हमारी निंदा कर रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमको लोगों के बीच में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों की मदद करनी पड़ती है, इसी वजह से हमारा भी संक्रमण होता है और हमें भी इस संकट से जूझना पड़ता है। एक बात समझी जानी चाहिए कि यह कोई राजनीति की लड़ाई नहीं है, अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाने की लड़ाई है और इसमें हर व्यक्ति को अपना योगदान देना है, तभी देश की तिबयत खुशनुमा रहेगी। हमारे मित्र डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे साहब यहां पर नहीं हैं, अगर आप उनका कल का पूरा भाषण सुनें, तो उनके पूरे भाषण में महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नहीं किया, महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से फेल है, उसकी सिर्फ निंदा की. खिंचाई की।

पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली सरकारें कुछ नहीं करती हैं, बाकी सब सरकारें ठीक कर रही हैं, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में 30 हजार से भी ज्यादा Corona संक्रमित मरीज recover हो गए, यह कैसे हो गया? क्या पूरे देश में ये सभी भाभी जी के पापड़ खाकर ठीक हो गए? ऐसा नहीं है। पूरे देश में, सभी राज्यों में, सभी राज्य सरकारें अपनी-अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही हैं। हमने पहले दिन कहा था कि यह जो लड़ाई है, हम यह लड़ाई प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं। वे देश के नेता हैं और इतना बड़ा संकट है, तो लड़ाई प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में ही लड़नी चाहिए। हमने पूरा protocol follow किया है। हमारी महाराष्ट्र सरकार ने प्रधान मंत्री जी के निर्देश में ही follow किया है। हमारे माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर जी यहाँ बैठे हैं, आप उनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री जी ने खास कर महाराष्ट्र में पूरे जिले का coordination करने के लिए प्रकाश जावडेकर साहब को appoint किया है। उनका राज्य सरकार के साथ और मुख्य मंत्री के साथ ठीक तरह का coordination चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, ठाणे, पुणे जैसे बड़े शहरों में नहीं, बल्कि जिला स्तर पर jumbo COVID Centre बनाए हैं और वह लोगों की सेवा में लगी है।

महोदय, देश और महाराष्ट्र राज्य को सबसे ज्यादा चिंता हमारे यहाँ की धारावी स्लम बस्ती की थी। धारावी, जो Asia का झुग्गी-झोंपड़ी का एक बहुत बड़ा इलाका है, उसको लेकर चिंता थी कि अगर वहाँ कोरोना वायरस घुस गया, तो क्या होगा? जब वहाँ पर कोरोना संक्रमण हुआ था, तो पूरा देश चिंता में आ गया था, लेकिन आज धारावी का संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है और World Health Organization अर्थात् W.H.O. ने इसके लिए हमारी बीएमसी की पीठ थपथपाई है।

महोदय, मुंबई का हमारा दूसरा इलाका वर्ली कुलीवाड़ा है, वहाँ पर fishermen community सबसे ज्यादा रहती है। वह बहुत congested area है। जब वहाँ भी संक्रमण बढ़ा था, तो सब विंता में आ गए थे, लेकिन वहाँ के जो हमारे विधायक और मंत्री आदित्य ठाकरे जी हैं, उन्होंने वहाँ का पूरा संक्रमण खत्म किया है। हमारे जो Health Minister डा. हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने भी इसके लिए उन्हें शाबाशी दी है।

महोदय, आरोप लगाना ठीक है, लेकिन जो काम करते हैं, आप उनको भी देखिए। अगर मैंने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में - मैं मानता हूं कि चेतन चौहान साहब जैसे बड़े क्रिकेटर की मौत हो गई। मैं उस बारे में वहाँ की विधान परिषद् के एक नेता का भाषण सुन रहा था। वहाँ की जो अव्यवस्था है, उसकी वजह से चेतन चौहान साहब की मौत हो गई, विधायक ने इस प्रकार का आरोप लगाया है, लेकिन यह आरोप लगाने का वक्त नहीं है।

महोदय, दूसरी बात यह है कि एक आरोप वहाँ से भी लगाया गया कि महाराष्ट्र राज्य में पाँच हजार नए हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स की recruitment नहीं हुई। इस बात को समझना चाहिए कि हमारी सरकार को आए छह या सात महीने हुए हैं, लेकिन इनसे पहले पाँच साल से किसकी सरकार थी? हमारे देवेन्द्र जी की सरकार थी। अगर आप पिछले पाँच सालों में इन 5,000 डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट कर देते तो आज बहुत बड़ा infrastructure खड़ा होता। हमें यह बात भी समझनी चाहिए और हमें या आपको एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए।

महोदय, आपने हिसाब-किताब की बात की है। मुझे मालूम है कि अभी केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से पूरे medical equipments की मदद देनी बंद कर दी है। PPE kit, mask, ventilator की वजह से महाराष्ट्र सरकार के ऊपर अब 350 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ने वाला है। आपने जो PM CARES Fund बनाया है, उसमें जो हज़ारों करोड़ रुपये CSR funds से जमा किए हैं, वे रुपये किसके लिए हैं? वे सभी राज्यों के लिए हैं, वे आपको देने पड़ेंगे।

महोदय, एक अन्य बात यह है कि हमारा जो GST का बकाया है, आप उसको तो दे दीजिए। हम उससे आगे का काम चला लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि राज्य सरकार COVID की लड़ाई अपने आप लड़े, तो आपके पास हमारा जो बकाया पड़ा है, वह आप हमें दीजिए। मैं सभी राज्यों की बात करता हूं।

महोदय, मैं महाराष्ट्र सरकार के बारे में बताना चाहता हूं कि मार्च महीने में, जब कोविड का संकट शुरू हुआ, तो पूरे राज्य में सिर्फ एक testing lab थी, लेकिन आज हमने, इन पाँच महीनों में पूरे महाराष्ट्र में 405 testing labs खड़ी की हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: माननीय संजय जी, आप conclude कीजिए।

श्री संजय राउत: उपसभापति जी, मैं conclude करता हूं।

महोदय, बात ऐसी है कि ...(व्यवधान)... मैं mask तो लगाऊंगा, केंद्र सरकार ने देना बंद कर दिया है, इसलिए.. ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आपने अच्छा किया है। चेयरमैन साहब ने अभी बताकर हम सबसे आग्रह किया था।

श्री संजय राउत: बात ऐसी है कि केन्द्र सरकार के 7 मंत्री संक्रमित हुए हैं। यह किसी के ऊपर नहीं है कि आप कौन से राज्य से आते हैं। आज मैंने सुना है कि हमारे नितिन गड़करी जी संक्रमित हुए हैं। मैं उनके जल्दी ठीक होने की कामना करता हूँ। दूसरी बात, आज देश में संक्रमण का आँकड़ा 50 लाख से भी ज्यादा ऊपर गया है, 80 हजार से ज्यादा मौतें हो गई हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि इस पूरी लड़ाई में पूरे देश, सभी राज्यों को साथ लेकर हमें आगे की लड़ाई लड़नी होगी। हम एक-दूसरे के खिलाफ सिर्फ राजनीति करने बैठेंगे, तो यह 50 लाख का आँकड़ा एक करोड़ तक पहुँच जाएगा। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से सबसे, सभी राजनीतिक दलों से, सभी सरकारों से विनती करता हूँ कि जब तक आखिरी कोविड पेशेंट ठीक नहीं होता, तब तक हम एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम करेंगे।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद संजय जी। माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी। तीन मिनट प्लीज़। ...(व्यवधान)... कृपया बीच में न बोलें।

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र): सर, मैं राज्य सभा चैम्बर से बोल रहा हूँ।

सर, यह विश्व का सबसे बड़ा pandemic है, महामारी है, 1918 के फ्लू के बाद, जिसमें करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। यह केवल हमारे देश के लिए ही नहीं, बिल्क विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। जिस मात्रा में हमारे देश में लोगों की मृत्यु हुई है, जिस मात्रा में विश्व में मृत्यु हुई है, मैं अपनी ओर से और हमारे पक्ष की ओर से, NCP की ओर से जो सारे मृतक हैं, उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, paramedics हैं, सफाई वर्कर्स हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं या जिन लोगों ने इस महत्वपूर्ण लड़ाई में हम सब लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपना योगदान दिया है, मैं उनको भी नतमस्तक होकर salute करना चाहता हूँ।

डिप्टी चेयरमैन सर, इस महामारी की कोई दिशा निर्धारित नहीं है। इसकी शुरुआत शहरों से हुई। पहला केस जनवरी में प्राप्त हुआ। तब लगता था कि रोज़ के कोई 5-10-50-100 केस आते थे। अब बढ़ते-बढ़ते आज हम हर रोज़ एक लाख केसों तक पहुँच चुके हैं। जो अनुमान लगाया गया है, कई अखबारों में मैं कल भी पढ़ रहा था कि कम से कम 2-2.5 लाख केस रोज

होने जा रहे हैं, हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं। इसलिए इसकी लड़ाई लड़ने में हम सबको संयुक्त होने की जरूरत होने वाली है। मेरे मित्र, संजय जी ने अभी जो कहा, इस लड़ाई की शुरुआत से केन्द्र सरकार के निर्देश के अनुसार सभी राज्यों ने इसका अनुसरण करने का काम किया। आज भी जो unlock होता है, stages में Central Government की Ministry of Home Affairs की जो guidelines आती हैं, उनके आधार पर सभी राज्यों ने अपनी unlocking की प्रक्रिया की शुरुआत की है। इसलिए दोषारोपण, जैसा ये कह रहे थे, वह बिल्कुल सही है। कल मैं भी सुन रहा था। कुछ बात ऐसी हो रही थी कि कुछ राज्य ऐसा कर रहे हैं, कुछ राज्य वैसा कर रहे हैं। उस वक्ता ने व्यक्तिगत रूप से मेरा नाम भी लिया था, इसीलिए में कहना चाहता हूँ कि जब हम सब लोग मिल कर इस लड़ाई में साथ में हैं, तो इसमें इस वक्त कोई टीका-टिप्पणी, दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आज अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो मुम्बई है, पुणे है, टाणे है, ...

श्री उपसभापति: प्रफुल्ल जी, कृपया conclude करें।

श्री प्रफुल्ल पटेल: देश के बड़े शहरों में, जहाँ इसकी तकलीफ है, तो क्या इन शहरों ने गलती की है कि पूरे देश के लोगों को अपना घर बनाने के लिए, वहाँ बसाने के लिए मौका दिया है? क्या यह उनकी गलती है? क्या उनके ऊपर टीका-टिप्पणी होगी? हमारे राज्य को किसी ने आकर PoK बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, क्या उसको हम सहन करेंगे? मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आज बहुत सारी समस्याएँ हैं। आज Remdesivir जैसी दवाई और ऑक्सीजन के सिलिंडर्स की कमी है। कल मैं बयान पढ़ रहा था कि ऑक्सीजन के सिलिंडर्स की कोई कमी नहीं है।

श्री उपसभापति: प्रफुल्ल जी, कृपया conclude करें।

श्री प्रफुल्ल पटेल: मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज रूरल एरियाज़ में ऑक्सीजन के सिलेंडरों की बहुत ज्यादा कमी है, Remdesivir की कमी है। आज भी अगर एक तरीके से इन सारी परेशानियों के लिए हमने सामूहिक तौर पर लड़ाई नहीं लड़ी, तो कल समस्या और भारी हो सकती है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आज राज्य सरकारों के पास निधि का अभाव है। निधि का अभाव कई कारणों से है। हमारी आय कम हो गई है, क्योंकि छ:-सात महीने से लॉकडाउन रहा है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्लीज़ कन्क्लूड करें, अदरवाइज़ मैं दूसरा नाम बुलाऊंगा।...(व्यवधान)...

श्री प्रफुल्ल पटेल: केन्द्र सरकार से मिलने वाला जीएसटी का पैसा हमें अभी तक नहीं मिला है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी।...(व्यवधान)... Nothing will go on record now. ...(Interruptions)...

## श्री प्रफुल्ल पटेल: \*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Priyanka Chaturvedi, you have three minutes. ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record now. (*Interruptions*)... Shrimati Priyanka Chaturvedi, please speak.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, I am speaking form Lok Sabha. I am sorry, I will have to take off the mask because I want to be clear about what I am speaking with all due respect to the hon. Deputy Chairman.

श्री उपसभापति: कृपया मास्क पहन लें।...(व्यवधान)...

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी: सर, मैं इसको साफ कर दूंगी, लेकिन मास्क पहन कर वॉयस की क्लैरिटी में दिक्कत होगी।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः प्रियंका जी, माननीय चेयरमैन साहब ने कहा है, कृपया मास्क लगा लें। श्री प्रफुल्ल पटेल: \*

श्री उपसभापति: जो टाइम एलोकेटेड है, उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं।...(व्यवधान)... प्लीज़...(व्यवधान)... Nothing will go on record. Mr. Patel, I am not allowing you. ...(Interruptions)... Priyankaji, please speak. ...(Interruptions)...

### श्री प्रफूल्ल पटेल: \*

श्री उपसभापतिः आपने चार मिनट लिए हैं।...(व्यवधान)... Nothing is going on record. ...(Interruptions)... Nothing is going on record. ...(Interruptions)...

### श्री प्रफुल्ल पटेल: \*

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I would like to thank you for giving me the time to speak on a very important subject, which is impacting not just the State of Maharashtra but every single resident of every single State. Yesterday, it was very disappointing that on one hand my fellow MP continued to say that let us not politicise it, but continued to politicise the entire issue of Covid and made the response very State-specific. At a time when we are fighting the entire Covid response, seeing this kind of behaviour was very disappointing to say the least for a first time MP like me. I would like to ask the Union Health Minister, in his statement two days ago, he had specifically mentioned some States which are giving maximum case loads.

<sup>\*</sup>Not recorded.

On that, I would specifically wish to ask him, considering that under the Epidemic Act, everything has been brought under the control of Government of India, what is the specific State response that these States which are facing the maximum case load getting? My second question to the Health Minister which has already been made by my senior leader, Shri Sanjay Raut, is that every State Government has now been asked to handle the requirements for equipments such as PPE kits, testing kits and ventilators for their States, considering the State Governments are already under tremendous financial burden of not getting their due GST, how do you expect the State to give its response in the way it is needed?..(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Priyankaji, kindly conclude. ...(Interruptions)...

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, I will conclude. He had mentioned in passing that Covid cases and surgeries that are non-Covid related, are being taken care of. But the truth...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Priyankaji.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Just 30 seconds, Sir. More than a million children have missed crucial immunisation, and hospital births have shown a sharp decline indicating many women may have gone through unsafe child birth at home.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Priyankaji. Please conclude.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Just 30 seconds more. Outpatient critical care for Cancer has plunged to 80 per cent...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Priyankaji, please conclude. I will call the other speaker now. ...(*Interruptions*)... Please.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, we have important questions. These cannot be wrapped up in three minutes. I need another ten seconds to just speak about. ...(Interruptions)... Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Kanakamedala Ravindra Kumar.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Thank you Deputy Chairman, Sir, for giving this opportunity. Two days before the hon. Minister gave a detailed statement regarding the outbreak of Corona Virus and the steps taken

# [Shri Kanakamedala Ravindra Kumar]

by them. Now, I come to the Andhra Pradesh. The situation of pandemic is very high in the State of Andhra Pradesh. It is in second place after Maharashtra as per the statement given by the hon. Minister. The attitude of the incumbent Government is such that the Chief Minister announced that the Covid-19 pandemic will be dealt by using Paracetamol and bleaching powder contents alone. This shows the negligent attitude of the State Government.

The figures being shown in record are under-reported. Actually, the number of persons affected with Covid-19 is very high. The hon. Chief Minister of Andhra Pradesh has to raise the level of making Paracetamol and bleaching powder in order to rescue the people from greater danger of Covid. My deep concern is Andhra Pradesh has now stands at second place in recording the highest number of Coronavirus cases in the country. The rising infections are creating fears among the people of all sections. As per latest Covid-19 latest tracker, Andhra Pradesh stood at the second place with the active cases of almost around 6 lakhs and more than 5,000 people are died. The unchecked rise in covid cases in Andhra Pradesh to the unofficial and unauthorized and meetings that took place in the State. The Government could not control crowds at liquor shops which led to serious infections. The Government also failed to regulate and check Coronavirus threat at the quarantine centres. Now, the Andhra Pradesh Government had taken a vindictive attitude against doctors also. As far as Vizag is concerned, one Dr. Sudhakar's hands were tied with rope and false cases were filed against him on the ground that he stated that PPE kits were not provided to him despite being a frontline Corona warrior. Likewise, one private hospital doctor, Dr. Ramesh was also victimized and against him also, a false case was filed due to unfortunate incident of fire accident. The Central Government has sent the teams to some of the States. To my knowledge, in Andhra Pradesh, no Central team has been sent so far. In view of the present severe condition in the State of Andhra Pradesh, I request and urge upon the hon. Minister to send the teams to the State of Andhra Pradesh to take control of the situation because the State Government has neglected and no facilities are being provided in the quarantine centres, no facilities are being provided in isolation centres. Now, the patients are terrorised. Most of patients come on roads and are conducting dharnas. Now, the situation is very.....(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ravindra Kumarji, please conclude.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, I will take half a minute only. As far as the State is concerned, a clinical trial is also going on. The Central Government has not given any instructions to the Government of Andhra Pradesh. I request the Central Government has to take appropriate steps in order to reduce the cases in the State of Andhra Pradesh by sending a Central team to the State of Andhra Pradesh and direct the State Government not to harass the doctors and also corona patients and to give proper treatment.....(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Instead of victimizing the political opponents, it is better to concentrate on controlling the Covid cases. I request the hon. Minister to supervise directly in view of the special circumstances prevailing in the State of Andhra Pradesh. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Binoy Viswam.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): From Gallery No. 4, Rajya Sabha, I am Binoy Viswam.

Sir, on behalf of my party, the Communist Party of India, I appreciate the pains taken by the hon. Health Minister, a sincere effort, I should say, to make a statement that contains 11 pages of the steps taken by the Government to fight the pandemic. But, I am sorry to say that in that long, long statement, not even a single word has been mentioned about the State of Kerala. The country and the world know that Kerala did play a vital role in fighting the Covid in an effective manner. We still have problems. But, in a statement like this, the nation should have taken note of that. This is my first remark. Sir, the situation is really alarming for the whole country. Our Prime Minister always talks about the fastest growing economy. Fastest growing economy of the world is India; fastest developing arms supplier is India; fastest growing toy hub is India; everything is fastest here. And, now we have become the fastest declining economy also. In the fight against Covid, other matters are also very important. The social impact, economic impact, human impact, all such matters are missing in the statement. That is a humble remark that I want to make in this regard. How can the Government forget about the migrant labourers who were dying on the roads on those days? They are the martyrs of the Covid. What measures did we take to support them, to ensure their survival? Sir, a responsible Government has the duty to show concern for the poor. Sir,

[Shri Binoy Viswam]

the Covid days proved one thing to us -- think about the poor. They were the real fighters. They fought for the country. They have fought for all of us. They include, the doctors, the nurses, the paramedics not only these people, but, the Safai Karamcharis. Even the sweepers played a role. Their role was very, very clear in the days of pandemic and the country has to take note of it. I believe that the Minister of Health and Family Welfare will make a mention of them when he makes his reply. Sir, here, I want to mention one more point. The exorbitant charges in the private hospitals are really alarming and the Government should intervene in this matter. The five star private hospitals are plundering the people in the name of Covid. That should not be allowed. Sir, we must see to it that the efficiency and potential of all systems of medicines are captured.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Binoy Viswamji.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I would take just one more minute. Homoeopathy has got a potential, Ayurveda has got a potential, Siddha, Naturopathy, Yoga -- all have got the potential in prevention of such a pandemic situation. That exploration has to be strengthened by all means and the Government has to initiate that with all means. Sir, there was news about the deficiency of oxygen cylinders in the country. It is now being discussed in the whole Indian sub continent, it is a real problem.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BINOY VISWAM: So, I request the Government to ensure that enough number of oxygen cylinders are available and necessary ventilators are also available. I remember, I was the first among many Members here to ask for masks for everybody.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRI BINOY VISWAM: I repeat it. Sir, we should try to give free masks to all the poor people. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Shri Binoy Viswamji. Now, the next speaker is Shri G K. Vasan.

SHRI G. K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, today, our country has crossed 50 lakh mark in respect of confirmed cases and crossed the 75,000 mark in case of deaths. However, Sir, I would like to say with the concerted efforts of the Union and State Governments

and the responsible behaviour of the people of our country in terms of building immunity and adopting safety measures, we have been able to achieve high recovery rate cases and we have been able to maintain our death rate at the least. Sir, the Central Government today has been spreading the message of hope among our countrymen. The Ministry of Health and Family Welfare has been closely reviewing the situation on all aspects with its counterparts in States and Union Territories. Sir, I come from the State of Tamil Nadu. The Government of Tamil Nadu, I would like to say, is doing an effective management of COVID-19 pandemic by taking all proactive steps. The State has done the maximum number of tests in the country compared to any State. Tamil Nadu is one among the States where the death rate due to COVID-19 cases is the least. Sir, to conclude the frontline health workers and COVID-19 care-givers have stood by us in this unfolding scenario. I salute the COVID-19 warriors for their dedication, which is a major contributing factor in the 77 per cent recovery of confirmed cases that we talk about. Sir, the last point, every individual in India today realizes the safety practices. Of course, there are aberrations, a few instances of crowded gatherings. We have to correct ourselves and return to the path of safety in maintaining all the protocols required to keep the Coronavirus at bay and stop the spread of this disease. Thank you, Sir.

[17 September, 2020]

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभापित महोदय, कोविड-19 का भारत में बेरोजगारी व अर्थव्यवस्था पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन के कारण मई, 2020 तक देश में बेरोजगारी दर 24 प्रतिशत हो गयी है, जिसका मुख्य कारण माँग में कमी के साथ-साथ कंपनियों द्वारा बड़ी संख्या में कार्यबल की छँटनी भी है। सिर्फ अप्रैल महीने में 27 मिलियन से अधिक युवाओं के नौकरी खोने के कारण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर दिखा है। देश में 15 सितम्बर, 2020 तक कुल बेरोजगारी दर 7.7 प्रतिशत थी, जो कि शहरी क्षेत्र में 9 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 7 प्रतिशत थी। इसका प्रमुख कारण मुख्य रूप से कृषि रोजगार आधारित अर्थव्यवस्था है, जहाँ रोजगार, कृषि, विनिर्माण और सेवाओं का मिश्रण है।

महोदय, महामारी से देश की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुँची है, अपितु इसकी सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ी है। एक तरफ रोजगार के अवसर कम हुए हैं, तो दूसरी तरफ आवश्यक सामान के दाम बढ़े हैं। माँग खत्म होने से बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग बेरोजगार हुए हैं। महोदय, आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से गैर-जरूरी और आवश्यक सामान की कीमतों में वृद्धि हो रही है और समाज में एक नई तरह की असमानता उपजी है विशेषकर आर्थिक, सामाजिक शोषित वर्ग के समाज में। ऑफिस में काम करने वाले पेशेवर लोग घर से काम कर रहे हैं, जबिक मजदूर और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को बाहर जाना पड़ता है, इससे इनके कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बढ़ा है।

[श्री वीर सिंह]

महोदय, मैं सरकार से माँग करता हूँ कि कोरोना के चलते भारी बेरोजगारी से निपटने हेतु सरकार श्रम सुधार के बड़े कदमों के साथ महिला श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करे, कृषि क्षेत्र में निर्माण बढ़ावे, उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए एमएसएमई की सहूलियत दे और सरकारी बैंकों को अतिरिक्त पूँजी निर्गत करे।

महोदय, आज हमारे देश में कोरोना के कारण लगभग 24 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार खोना पड़ा है। कोरोना के कारण इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि 84 प्रतिशत घरों में उनकी मासिक आमदनी कम हो गई है, क्योंकि सारा कारोबार उप हो गया है। केन्द्र सरकार के द्वारा जो बिना तैयारी के लॉकडाउन किया गया, उससे लोगों को बहुत परेशानी हुई। अगर यही लॉकडाउन एक सप्ताह पहले किया जाता, चूँकि जनवरी में पहला केस आ गया था, इसलिए अगर इसकी तैयारी उसी समय से होती, तो यह परेशानी नहीं होती। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी मजदूरों को उठानी पड़ी, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ, तब उनका रोजगार छीना गया, कंपनियों ने उनको निकाल दिया, तो उनको अपने घर जाने के लिए विवश होना पड़ा। जाने के लिए कोई साधन नहीं था, तो वे पैदल चल दिए। इसके कारण गरीब लोग कोरोना से कम, भूख से ज्यादा मरे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को गरीबों की तरफ ध्यान देना चाहिए।

महोदय, आज इसके लिए पूरे देश में जो प्राइवेट अस्पताल चिन्हित किए गए हैं, उनमें बुरा हाल है। वहाँ गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है। उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं। जो पैसे वाले लोग हैं या प्रभावशाली लोग हैं, उनकी तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर व्यवस्था हो जाती है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। वहाँ पर सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, पर प्रयास असफल हो रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है और खास करके वहाँ पर गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसके कारण आज बेचारा गरीब कोरोना के कारण मर रहा है।

श्री उपसभापति: वीर सिंह जी, आप conclude कीजिए।

श्री वीर सिंह: महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि जो प्रवासी मजदूर हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि आज वे बेराजगार हो गए हैं, उनको कंपनियों से निकाला गया। वे अपने गाँव गए, तो इस सरकार के द्वारा कहा गया कि गाँवों में उनको रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उनको गाँवों में आज तक रोजगार नहीं मिला। गाँवों में उनका घर भी नहीं है, क्योंकि वे 5-10 सालों से बाहर रह रहे थे, इसलिए आज वे परेशान हैं और दर-दर भटक रहे हैं। इसलिए मेरी सरकार से माँग है कि कोरोना काल में गरीबों के सामने जो मुसीबत आई है, उस ओर ध्यान दिया जाए।

महोदय, आज पूरे देश में कुपोषण का प्रभाव बढ़ रहा है, इस कारण से आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। मेरी यह माँग है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, वीर सिंह जी। श्री बिस्वजीत दैमारी। वे उपस्थित नहीं हैं। माननीय संजय सिंह जी।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): उपसभापित महोदय, कल से इस कोरोना की महामारी के विषय में चर्चा हो रही है और सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से तमाम आरोप-प्रत्यारोप इस महामारी के दौरान भी किए गए। यह बताने की कोशिश की गई कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है और एक सदस्य की शिकायत थी कि जब हम ताली, थाली बजा रहे थे, जब हम दीया जला रहे थे, तब विपक्ष वालों ने साथ नहीं दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि दुनिया की एक रिसर्च बता दीजिए, जिससे ताली और थाली बजाने से कोरोना ठीक होता हो। अगर इससे कोरोना ठीक होता हो, तो सारा विपक्ष मिल कर प्रधान मंत्री जी के साथ, हम लोग घर नहीं जाएँगे, ताली बजाएँगे, थाली बजाएँगे और शाम होगी, तो इसी संसद के परिसर में दीये जलाएँगे, लेकिन आप इससे एक कोरोना मरीज को ठीक करके दिखाइए। आप ऐसी मूर्खतापूर्ण योजनाओं को लेकर आते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपके साथ पूरा देश मूर्ख बन जाए।...(व्यवधान)... दूसरी बात, दूसरी बात...(व्यवधान)... चिल्लाइए मत, विल्लाइए मत, सूनिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़, प्लीज़...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, दूसरी बात, प्रधान मंत्री जी ने कहा, आपदा में अवसर तलाशिए।...(व्यवधान)... आपदा में अवसर तलाशिए।...(व्यवधान)... कल देरेक ओब्राईन जी कह रहे थे...(व्यवधान)... मुख्यमंत्रियों की तारीफ नहीं हुई।...(व्यवधान)... मुख्यमंत्री की तारीफ कैसे करेगी यह सरकार?...(व्यवधान)... हमारे \* एक ढोंगी बाबा है, उसने oximeter खरीदे हैं।...(व्यवधान)... 800 का oximeter 5,000 में खरीदा है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: कृपया मूल विषय पर बात करिए।...(व्यवधान)... किसी राज्य पर टिप्पणी करने के बजाय मूल विषय पर बोलें।...(व्यवधान)... संजय जी, मास्क लगा लीजिए।...(व्यवधान)... कृपया मास्क लगा लीजिए।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, 800 का oximeter 5,000 में खरीदा।...(व्यवधान)... सर, मैं फिर बता रहा हूँ कि 800 का oximeter...(व्यवधान)... \* 75 जिलों में घोटाला हुआ।...(व्यवधान)... 800 का oximeter 5,000 में खरीदा गया, 1,600 का थर्मामीटर 13,000 में खरीदा गया। ये लोग आठ-आठ सौ परसेंट कमीशन खा रहे हैं।...(व्यवधान)... आपदा में अवसर तलाश रहे हैं।...(व्यवधान)... \* ...(व्यवधान)...

<sup>\*</sup>Expunged as ordered by the Chair.

श्री उपसभापति: संजय जी, कृपया इस आरोप-प्रत्यारोप के बदले विषय पर बात करें।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, गुरुग्राम में ventilator जल गया।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः यह पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।...(व्यवधान)... कृपया विषय पर बात करें।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, मैं मानवता के मुद्दे पर बात कर रहा हूँ।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप अन्य राज्य सरकारों पर टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: श्मशान में दलाली खा रहे हैं ये लोग...(व्यवधान)... मान्यवर, ये लोग श्मशान में दलाली खा रहे हैं।...(व्यवधान)... भ्रष्टाचार कर रहे हैं सर...(व्यवधान)... भ्रष्टाचार कर रहे हैं...(व्यवधान)... श्मशान में दलाली खा रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: कृपया...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: कल इसी सदन में आरोप लगाया गया, कोई नहीं बोला।...(व्यवधान)... दिल्ली की सरकार ने...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः संजय जी, यह गंभीर समस्या है।...(व्यवधान)... आप आरोप-प्रत्यारोप के बजाय इस संकट पर बात करिए।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, आप मौका ही नहीं दे रहे हैं।...(व्यवधान)... आप मौका ही नहीं दे रहे हैं।...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति**: आप बोलें।...(व्यवधान)... आप बोल ही रहे हैं।...(व्यवधान)... प्लीज़, प्लीज़...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: आप एक मौका नहीं दे रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं सर...(व्यवधान)... चिल्ला रहे हैं।...(व्यवधान)... भृष्टाचार करने वाले चिल्ला रहे हैं।...(व्यवधान)... भृष्टाचार करने वाले चिल्ला रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः मेरा सबसे आग्रह है कृपया...(व्यवधान)... संजय जी, आपका समय जा रहा है, आप continue करें।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, आपने उन्हें नहीं रोका, हमें रोक रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: हम सबको मना कर रहे हैं।...(व्यवधान)... हम लगातार सबको मना कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, इस आपदा के दौरान, जब पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, आप बीपीसीएल बेच रहे हैं, आप रेल बेच रहे हैं, आप सेल बेच रहे हैं, आप मुनाफे की कंपनियों को बेचने में लगे हुए हैं।...(व्यवधान)... आपने हिन्दुस्तान के मजदूरों को भुखमरी की कगार पर पहुंचा दिया है।...(व्यवधान)... सर, रेल में 80 लोगों की जान गई, 40 ट्रेनें रास्ता भटक गईं। आप वह दृश्य नहीं भूल पाएंगे, मुजफ्फरपुर के प्लेटफॉर्म पर एक छोटा-सा बच्चा अपनी माँ की बेजान जिन्दगी से बार-बार कपड़े हटा रहा था।...(व्यवधान)... यह दृश्य कैसे यह सरकार भूल सकती है?

श्री उपसभापति: कृपया अब खत्म करें।

श्री संजय सिंह: मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना में दिल्ली की सरकार ने अनुकरणीय काम करके दिखाया।...(व्यवधान)... हमने प्लाज्मा बैंक तैयार करके दिखाया।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: कृपया खत्म करें।...(व्यवधान)... मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा।...(व्यवधान)... आप ऑलरेडी चार मिनट...(व्यवधान)... खत्म करें, जल्दी खत्म करें।...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: सर, हम जिस राज्य से आते हैं।...(व्यवधान)... सर, एक मिनट तो दीजिए, हम अपने राज्य की तैयारियों के बारे में तो बता दें।...(व्यवधान)... सर, प्लाज्मा बैंक बनवाया।...(व्यवधान)... देश का, दुनिया का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर बनवाया।...(व्यवधान)... आज दिल्ली के मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और ये लोग शमशान में दलाली खा रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: धन्यवाद, धन्यवाद।...(व्यवधान)... संजय जी, अब कोई भी...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कोरोना में लूट कर रहे हैं।...(व्यवधान)... इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः माननीय वि. विजयसाई रेड्डी।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, the hon. Prime Minister, while first imposing lockdown, has categorically said *Jaan hain toh Jahan hai*. Sir, post-unlocking of the country, the Central Government's approach of balancing the lives and livelihood has been much appreciated by conducting regular meetings with the Chief Ministers to discuss strategies to reduce the spread of Covid. The hon. Prime Minister has also united the country emotionally. Despite the financial crisis and economic crisis, the Andhra Pradesh Government's strategy has been a three-pronged strategy which effectively reduces the sufferings economically and of healthcare.

[Shri V. Vijayasai Reddy]

There are three-pronged strategies. The first is testing. Andhra Pradesh stands at number one and it is testing almost 72,000 people per day which has made its rank No. 1, in number of tests per million, among the States with a population of more than three crores. Sir, in fact, I am one of the sufferers of COVID and I know the importance of early detection that can never be under-stated.

The next is the treatment. Anyone tested positive can get himself treated without paying a single penny under YSR Arogya Sri Scheme. Under this scheme, a person with an annual income of below ₹ 5 lakhs is given free COVID treatment. Sir, this scheme even covers private hospitals. This is the extent of benefit being given under this scheme to patients treated for COVID. Further, to assist patients, a system of help desks under Arogya Mitra has been set up in Andhra Pradesh.

Sir, the Government of Andhra Pradesh has planned to spend a whopping ₹ 15,337 crores for overhauling the entire healthcare infrastructure in the State. In the first phase, more than 4,900, out of a total of 7,458 health sub-centres, will get new buildings, while the rest 2,552 will be modernized.

Sir, one important issue I would like to bring to your kind notice. Despite the odds that Government of Andhra Pradesh has been receiving, both from economic point of view\* in terms of COVID treatment, Andhra Pradesh is much ahead.

Sir, a quite unusual and legally questionable decision –Andhra Pradesh is not only suffering economically and financially\*

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: How is it relevant, Sir?

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: ...anything relating to FIR filed by the police against...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir. what is this?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: ...the former Advocate General of the State and others...(Interruptions)...\*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject, Mr. Reddy.

<sup>\*</sup>Expunged as ordered by the Chair.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: It is indeed open to the High Court to grant a stay on investigation in extraordinary cases.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Vijayasai Reddyji, please speak on the subject.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: When political vendetta is alleged against the Government of the day...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Otherwise, I will move to the next speaker.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: ...that too by someone who had served the previous regime as a law officer...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Vijayasai Reddyji, please speak on the subject...(Interruptions)...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: ...the need for media coverage and public scrutiny is all the greater.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Vijayasai Reddyji, please speak on the subject.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: How the petitioner would benefit from the complete absence of any reportage is unclear? It prevents legitimate comment even to the effect that there is no substance in the allegations.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are discussing COVID. Please speak on that.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: That is what I am saying, Sir. \* the Government of Andhra Pradesh is providing the best treatment to COVID patients and is doing its best, Sir. In fact, the Government is supposed to impose gag order. But, in Andhra Pradesh, alternatively, \*...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: And, \*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: So, it has to be stopped.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Vijayasai Reddyji, please conclude. Otherwise, I will move to the other speaker.

<sup>\*</sup>Expunged as ordered by the Chair.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Thank you, Sir.

डा. सुधांशु त्रिवेदी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापित महोदय, आज हम जिस विषय के ऊपर इस सदन में चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे कई पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा कि वह विश्व की सबसे बड़ी महामारी है, परन्तु मैं कहना चाहूँगा कि अभी दो दिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह डिटेल दी थी कि इस समय विश्व के 215 देश इससे प्रभावित हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक ऐसी परिस्थित रही हो, जो एक साथ इतने ज्यादा देशों को प्रभावित कर सके, तो यह मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे व्यापक चुनौती है। This is the biggest challenge in the documented history of mankind. ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति: कृपया गैलरी नम्बर एक में बैठे सदस्यगण आपस में बात न करें, आपकी आवाज आ रही है।

डा. स्धांश्रु त्रिवेदी: आप समझ सकते हैं कि जब इतनी व्यापक चुनौती और इतनी गंभीर चुनौती है, तो उसका सामना करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए। हमें उसका सामना करने के लिए एक मनोबल चाहिए, यानी एक संकल्प चाहिए; फिर संसाधन चाहिए; उसके साथ-साथ सभी वर्गों के साथ समन्वय चाहिए और चूंकि यह प्राणघातक है, तो संवेदनशीलता भी चाहिए। उपसभापति महोदय, में यह भी थोड़ा बताना चाहूंगा कि चुनौती के सामने हम खड़े कहां थे। यदि आप देखें तो इस परिस्थिति में चाइना की परिस्थिति थोड़ी विचित्र, अलग और संदिग्ध है। यदि एक बार उसको छोड़ दें तो हम दुनिया के सबसे बड़े देश थे। दुनिया के सबसे बड़े देश ही नहीं, जहां आज भी दो-तिहाई से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। यदि वर्ष 2011 की जनसंख्या को मानें तो 27 प्रतिशत लोग आज भी निरक्षर थे, जो समझ ही नहीं सकते थे कि क्या लिखा हुआ है। आज भी below poverty line की संख्या, अब मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा कि वह इतने वर्षों तक क्यों रहा, यह अलग बात है, परंतु आज का यथार्थ यह था कि वह विश्व में सबसे अधिक है। आप समझ सकते हैं कि हम कहां पर खड़े हुए थे, जिस समय यह चुनौती शुरू हुई, क्योंकि हमारे कई सदस्यों ने कहा था कि वे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात को करना चाहते हैं। Chronology of the events देखें तो मैं क्रोनोलॉजिकल प्रक्रिया, यानी कालक्रमानुसार इस घटनाक्रम की व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं। इन सबके साथ हमारे पास उस समय केवल एक virology की लैब थी। आप समझ सकते हैं कि हम उस समय कहां खड़े थे, किस चुनौती के साथ खड़े थे और यह इतनी बड़ी चुनौती थी कि दुनिया के बड़े-बड़े शक्तिशाली देश जो चिकित्सा सुविधाओं के बड़े-बड़े केन्द्र माने जा रहे थे, अमेरिका, ब्रिटेन और इटली तक इस तूफान के आगे भरभरा कर गिरते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इतना ही नहीं, माननीय उपसभापति महोदय, हमारा ही देश एक ऐसी विचित्र परिस्थिति में भी था, जहां स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले हो रहे थे, जिसके बचाव के लिए हमें एक कानून तक लाना पड़ा। उस समय पीपीई किट का इतना उत्पादन नहीं होता था, क्योंकि आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि वह केवल अस्तपालों के आईसीयू में प्रयोग होती थी। सेनेटाइज़र और मास्क बहुत सीमित संख्या में बन रहे थे और दूसरी तरफ यह वैश्विक तूफान

सामने आकर खड़ा हो रहा था, इसलिए इससे लड़ने के लिए जो प्रथम संकल्प की आवश्यकता थी, तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 21 मार्च, 2020 को जब जनता कर्फ्यू का आह्वान किया और जब दीया और थाली का आह्वान किया था तो वह उसका प्रतीक था कि हम इस प्रबल तूफान के आगे कितनी निर्बल स्थिति में थे, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वे किन कारणों से थे। मुझे वही पंक्ति ध्यान आयी थी, जो यह है:-

"निर्बल से लड़ाई बलवान की, यह कहानी थी दीये की और तूफान की।"

हमारे कई मित्रों को बड़ी आपित थी कि साहब दीया जलाने से कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि क्या सामाजिक मनोविज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान को हम नहीं समझते? मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग यह कह रहे हैं, वे इतिहास भूल गए। क्या चरखा चलाने से अंग्रेज़ भाग जाने वाला था? नहीं! चरखा एक प्रतीक था।

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): आप क्या बात कह रहे हैं?

**डा. सुधांशु त्रिवेदी**: मैं जवाब दे रहा हूं। मान्यवर, आप मेरा जवाब तो सुनिए। चरखा एक प्रतीक था, जो महात्मा गांधी जी ने चुना, जो भारत की राष्ट्रीय चेतना था...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: कोई अन्य बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।...(व्यवधान)...

नेता विपक्ष (श्री गुलाम नबी आज़ाद): चरखे से यह बताना था कि देशी कपड़ा बने और विदेशी कपड़े का बहिष्कार करें...(व्यवधान)...

<sup>†</sup>قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد): چرخے سے یہ بتانا تھا کہ دیشی کپڑا بنے اور ودیشی کا بہشکار کریں۔

श्री उपसभापति: ठीक है, अब आप अपनी बात बताएं।

**डा. सुधांशु त्रिवेदी**: मान्यवर, सुनिए। मैं वही बात बताना चाह रहा हूं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: कृपया सीट पर बैठ कर अन्य सदस्य न बोलें। आपकी बात के अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। आप बोलें।

डा. सुधांशु त्रिवेदी: महात्मा गांधी जी ने चरखे को एक प्रतीक बनाया। वह प्रतीक बना संपूर्ण भारतीय जनमानस की भावनाओं का केन्द्रबिंदु और वहां से ब्रिटिश राज को उखाड़ने का एक संकल्प उठा था। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उस दीये को एक प्रतीक बनाया, जिसमें संपूर्ण राष्ट्र की चेतना समवेत् रूप में आकर इस लड़ाई से लड़ने के लिए आगे बढ़े। इसलिए †Transliteration in Urdu script.

[डा. सुधांशु त्रिवेदी]

में कह रहा हूं कि इस संकल्प के मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है। हमारे कई विरोधी अभी बोल रहे थे। संजय राउत जी ने कहा कि हमारे पूर्व वक्ता डा. विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने महाराष्ट्र सरकार पर बात की। क्या हमें कुछ कहने की आवश्यकता है? उपसभापित महोदय, आपने इसी सदन में देखा कि महाराष्ट्र सरकार के दो घटक दलों के बीच का मनोभाव कैसे उभरकर सामने आ गया कि मेरा हिस्सा ज्यादा कि तेरा हिस्सा ज्यादा। मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ कहने की आवश्यकता है। संजय सिंह जी अभी बोल रहे थे। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आनन्द विहार के बस डिपो के पास खड़ी हुई भीड़ ही नहीं... उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री जी का उल्लेख नहीं होता। यदि आपको याद होगा और दिल्ली के मुख्य मंत्री के आपने वे तमाम वीडियोज़ भी देखे होंगे, मुझे याद है, उन वीडियोज़ में वे कहते थे कि 70 लाख लोगों का भोजन बन रहा है। हम सभी लोग दिल्ली में रहते हैं, हमको पता है कि वह 70 लाख लोगों का भोजन कहां बनता था और कहां पैक होता था, हम में से बहुत लोगों को शायद दिखाई नहीं पड़ा। खैर, मैं उस विषय को जाने देता हूं और इस बात पर आगे बढ़ता हूं कि हम रचनात्मक आलोचना का स्वागत करते हैं। आपको जो criticism करना है, वह criticism बिल्कुल करिए, परन्तु जब शुक्त से ही विषय कटाक्ष और व्यंग्यकर है, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत उचित नहीं है।

सर, सर्वप्रथम आवश्यकता संकल्प की थी, जिसको प्रधान मंत्री जी ने आगे बढ़ाया है। अब दूसरा विषय देखिए। अभी आपने देखा कि हमारे कई विरोधियों ने कहा है कि नमस्ते से बड़ी समस्या होती है। कल भी इसी सदन में कहा था कि साहब, नमस्ते का कार्यक्रम बड़ा भारी पड़ गया। मैं पूछना चाहता हूं कि नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम यदि भारी पड़ गया, दो घंटे में कुछ लोग थे, वह तिथि तो आप सबको ध्यान होगी, 24 फरवरी थी। उसी समय पूरे देश के दर्जनों शहरों में बकौल हमारे विरोधियों के लाखों लोग, हजारों की संख्या में बगैर social distancing का पालन करते हुए, जो कार्यक्रम कर रहे थे, क्या वह कोविड किलिंग ऑर्केस्ट्रा था? वह क्या था? यानी एक-दो घंटे के कार्यक्रम से सारी समस्या थी और वे स्वयं कह रहे थे कि जो सब तरफ चल रहा था, उससे कोई समस्या नहीं थी। यह एकांगी दृष्टि है, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए और एक यर्थाथ चीज को देखने का प्रयास करना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में अक्सर हमारे विरोधी लोग, विरोधी दल के प्रमुख नेता की दूरदृष्टि की बड़ी गवाही देते हैं। इनके नेता के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फरवरी के महीने में ही टिवट कर दिया था कि साहब, COVID कितनी बड़ी समस्या है और सरकार ने समय रहते उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। ऐसा कहा जाता कि उन्होंने 12,13 फरवरी को ट्वीट किया था। वे चिर युवा और चिर व्याकुल नेता हैं, परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि दूरदृष्टि कितनी दूर से आ रही थी। आप उस काल-खंड में देख लीजिए, जब वे यह बता रहे थे कि भारत सरकार को विदेश की फ्लाइटें बंद कर देनी चाहिए थीं, वह भी बहुत भयानक रूप धारण करता चला जा रहा है, तो वे उस समय स्वयं विदेश में थे। खैर, कोई बात नहीं। जब आए, तो हमें इस सदन में सब याद है। उनको यहां आने के बाद 12. 13 फरवरी को इतनी भयानक समस्या लगने लगी थी और

उनकी अप्रतिम ज्ञान सम्पन्न बुद्धि को इसका साक्षात्कार हो गया था, तो मार्च के प्रथम सप्ताह में सदन को रोक कर कोविड पर चर्चा करवाने की बात क्यों नहीं की गई? सदन दो दिन तक नहीं चला, किसलिए? कोविड पर चर्चा के लिए नहीं, वह बजट सत्र था। वह सत्र आर्थिक विषयों पर चर्चा के लिए नहीं था, उस तथाकथित बेरोज़गारी के लिए नहीं था, बेरोज़गारी का विषय है, जो कि उस समय आया था। उसके लिए नहीं था, किसके लिए था, दिल्ली की साम्प्रदायिक हिंसा के लिए। यानी कहा यह जा रहा है, दिल्ली साम्प्रदायिक हिंसा पर discussion हुआ। उस सदन में 11 मार्च को और इस सदन में 12 मार्च को discussion हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब वास्तविकता था, तो आज जो कहा जाता है, मैं उसमें comparison नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या एक बार भी यह मुद्दा उठाया गया? इसलिए अब जब सरकार की केवल व्यांग्यात्मक, कटाक्षात्मक आलोचना करनी हो, तो इन विषयों को उठाना, मुझे तर्क- संगत नहीं लगता है। यह इनके आचरण से बहुत साफ दिखाई पड़ता है। ...(व्यवधान)... आपने मध्य प्रदेश में बड़ा अच्छा...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्लीज़, कृपया सीट पर बैठकर न बोलें।

डा. सुधांशु त्रिवेदी: चिलए, कोई बात नहीं उपसभापित महोदय, मैं इनकी बात का उत्तर आपके माध्यम से दे देता हूं। जब 4 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री ने इस सदन में बयान दिया था, तो उस समय भारत में कोविड के 29 केस थे। जिस समय मध्य प्रदेश का यह घटना क्रम है, उस समय को ध्यान कर लें। उस समय मध्य प्रदेश में कोविड का एक भी केस नहीं था। चिलए, कोई बात नहीं। जो मध्य प्रदेश में था, वहां कोविड की समस्या नहीं थी। वहां पर समस्या दूसरे प्रकार की थी। उसका कोरोना वायरस से कोई लेना-देना नहीं था। आपके यहां बहुत समय से वह वायरस प्रविष्ट किए हुए है।

श्री उपसभापति: आप कोरोना पर बोलिए।

**डा. सुधांशु त्रिवेदी**: सर, मैं अब दूसरी बात पर आता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप प्लीज़ कोरोना पर बोलिए।

डा. स्धांश् त्रिवेदी: उपसभापति महोदय...(व्यवधान)...

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please.

SHRI RIPUN BORA: Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Under which rule?

SHRI RIPUN BORA: Sir, I have a point of order under Rule 240. It is "Irrelevance or repetition". "The Chairman, after having called the attention of the Council to the conduct of a Member who persists in irrelevance ..." He is saying irrelevant things. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. I have seen it. ...(Interruptions)... I have seen it. ...(Interruptions)...

SHRI RIPUN BORA: Sir, this is 'Discussion on the Minister's statement'. But he is saying irrelevant things. ...(Interruptions)...

श्री उपसभापतिः मेरी यह रिक्वेस्ट सभी सदस्यों से है। कृपया follow this. ...(Interruptions)... मेरी यह रिक्वेस्ट सभी सदस्यों से है। प्लीज़।

डा. सुधांशु त्रिवेदी: अब मैं अपना विषय आगे बढ़ाता हूं। अगला प्रश्न यह किया गया कि चार दिन के लिए लॉकडाउन अचानक कर दिया गया। इसे विस्तार से करना चाहिए था, विचार करके करना चाहिए, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि हम सभी विद्वान सदस्यों को यह ज्ञात है कि हमारे यहां स्थिति यह थी कि उस समय तक सैनिटाइज़र भी बहुत कम संख्या में थे, संसाधन कम संख्या में थे, मास्क कम संख्या में थे और हम दुनिया के एकमात्र देश हैं, जहां रोज़ डेढ़ करोड़ लोग ट्रेन में चलते हैं। ऐसे आधे से ज्यादा दुनिया के देशों की आबादी उतनी नहीं है, जितना हमारे यहां प्रतिदिन लोग ट्रेन में चलते थे और इससे ज्यादा लोग राज्यों की परिवहन की बसों में चलते हैं। आप कल्पना करें कि यदि यह कहा जाता कि दो दिन के बाद सब कुछ होने वाला है, तो उस समय होने वाली अव्यवस्था, उस समय होने वाली भगदड़ और उस समय जो परिस्थितियां उत्पन्न होतीं, उसका सहज स्वाभाविक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे एकदम कोई वज्रपात होता है, तो उस समय आपके पास प्लानिंग करने का वक्त नहीं होता है, समय रहते उस पर कार्रवाई करनी होती है, इसलिए प्रधान मंत्री जी ने जो किया, यदि आप याद कर रहे हैं, तो उस समय के WHO ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसका अनुमोदन किया। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ जो गृह मंत्रालय के द्वारा जवाब दिया गया कि यदि लॉकडाउन देर से होता, तो 14 से 29 लाख लोग और प्रभावित हो सकते थे। 38 हजार से 78 हजार जानें जा सकती थीं। आदरणीय आनन्द शर्मा जी ने कल यह कहा था कि यह आंकड़ा बहुत variable है। मैं मानता हूं कि यह variable है, बल्कि मैं यह मानता हूं कि शायद गृह मंत्रालय ने बड़ी मितव्ययिता के साथ इस आंकड़े को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, अन्यथा आप समझ सकते हैं कि अगर आपने देखा हो, जब हमने अपनी आंखों से कोविड काल में देखा कि चाहे मुंबई का तिलक टर्मिनल हो या दिल्ली का आनन्द विहार हो, इतनी भीड़ हमने कोविड काल में देखी, तो आप कल्पना करिए कि यदि कह दिया जाता कि दो दिन बाद होने वाला है और अब आप सब जाइए, तो क्या परिस्थिति होती, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

सर, अब अगला प्रश्न आता है कि आप समन्वय कितना कर रहे हैं? अगला आरोप था कि समन्वय नहीं किया। मैं यह बताना चाहता हूं और आप सभी ने देखा कि प्रधान मंत्री जी ने सभी मुख्य मंत्रियों से निरंतर समन्वय किया, सभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की। इतना ही नहीं डॉक्टर्स के साथ, विषय के विशेषज्ञों के साथ, इतना ही नहीं कलाकारों, धर्माचार्यों, खिलाड़ियों, व्यावसायियों, उद्योगपतियों और किसी के भी साथ उन्होंने समन्वय करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। यानी सभी लोगों के साथ व समन्वय और अगर मैं यह कहूं कि समाज का कोई भी तबका ऐसा नहीं था, जिसे उन्होंने किसी भी प्रकार से छोड़ने का प्रयास किया हो, तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। मैं लॉकडाउन के decision के बारे में याद दिलाना चाहता हूं कि जिन लोगों को आपत्ति है कि जब लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 2 की तरफ जाना था, तो केन्द्र सरकार के द्वारा घोषित करने से दो दिन पहले जिन तीन राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, वे पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना थीं। इसका अर्थ बहुत साफ है और संयोग से ये तीनों विपक्ष की सरकारें हैं। अर्थ बह्त साफ है कि उस समय लॉकडाउन अपरिहार्यता थी और दलगत भावना से अलग हटकर अगर हम देखें, तो वह लॉकडाउन आवश्यक था और प्रधान मंत्री जी ने पूरे समन्वय के साथ आगे बढ़ाया और आपने देखा सिर्फ समन्वय इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वार्ता की, G-20 के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी वार्ता की और हम सब को वह दृश्य भी ध्यान होगा, जब प्रधान मंत्री जी ने एक सामान्य नर्स से बात की थी, तो उस नर्स का मनोभाव आप उस चित्र में देखते, तो वह देखते बन रहा था, जो कहीं न कहीं इस बात का प्रमाण था कि बड़े-बड़े राष्ट्राध्यक्षों से लेकर और एक सामान्य स्वास्थकर्मी तक प्रधान मंत्री जी समान रूप से समन्वय की बात कर रहे थे। कल हमारे तृणमूल कांग्रेस के नेता ने सदन में यह कहने का प्रयास किया बंगाल की मुख्य मंत्री जी ने एक अवेयरनेस का प्रयास किया था, जब उन्होंने ज़मीन के ऊपर सर्किल्स बनाए। यह अच्छा प्रयास था, पर उन्होंने यह कहा कि दूसरा दृश्य उन्हें याद नहीं आया, तो मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री के द्वारा ज़मीन पर सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश देते हुए सर्किल बनाने का दृश्य याद है, लेकिन प्रधान मंत्री के द्वारा स्वच्छता का संदेश देते हुए झाडू लगाने का चित्र याद नहीं था। प्रधान मंत्री के द्वारा समाज के सबसे वंचित तबकों का पाद प्रक्षालन, पैर धोने का दृश्य याद नहीं था। जब दृश्य याद करिए तो सारे याद करिए और वैसे तो देखिए तस्वीर की जहां तक बात है, तो मैं थोड़ा-सा कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री की भी एक बड़ी विशेष तस्वीर हुआ करती थी। जब हम लोग कोलकाता जाते थे, वह यत्र, तत्र, सर्वत्र दिखती थी। आजकल वह नहीं दिखती है और अब तो वह इंटरनेट पर भी आसानी से नहीं दिखती है। अब वह तस्वीर तसव्वूर में चली गई है, इसलिए वह अब हृदयपटल पर होगी और दृश्यपटल पर दिखाई नहीं पड़ती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब अगर हम आगे बढ़ें, तो समन्वय के साथ-साथ अगला प्रश्न आता है - संसाधन। हमने इन महीनों में क्या किया? हमने यह किया कि एक लेब थी और वहां से बढ़ते हुए हम 1705 लैब्स तक पहुंच गए हैं। आज देश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर कि कोविड की लेब उपलब्ध न हो, जबकि पहले स्थिति यह थी कि वह केवल एक थी - पुणे में। वह पूरे

[डा. सुधांशु त्रिवेदी]

देश में और कहीं नहीं थी और उस वायरोलॉज़ी के टैस्ट में कई दिन लगते थे। आज स्थिति यह है जैसा कि हैल्थ मिनिस्टर साहब ने बताया कि प्रति दिन 10.94 लाख टैस्ट्स किए जा रहे हैं। टैस्ट करने के मामले में इस समय भारत वैश्विक मानक से ऊपर चल रहा है। यहां एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। आज 1.93 करोड़ पीपीई किट बनने का आदेश है और 1.29 करोड़ पीपीई किट बन चुकी हैं। जहां तक दवाओं की बात है, हमने भारी मात्रा में दवाएं न सिर्फ यहां बनाई हैं, बल्कि तमाम देशों को एक्सपोर्ट भी की हैं। अगर आप यह देखें तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या अन्य दवाओं से साथ पहली बार एक संयोग भी रहा कि अमेरिका के एफडीए ने अपनी मार्किट में भारतीय दवाओं को मंजूरी दी, जबिक अभी तक भारतीय कंपनियों की दवाओं को वह मंजूरी नहीं मिलती थी।...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्माः सर, यह गलत बात है। ...(व्यवधान)... Sir, this is a factually wrong statement.

### MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please.

डा. सुधांशु त्रिवेदी: आज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के मामले में उन्होंने परिमशन दी कि मार्केट में वे सेल कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भारतीय कंपनियों को बुलाया। सामान्यत: वे भारत के किसी प्रोडक्ट को स्वीकार नहीं करते थे।

उपसभापति महोदय, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं। देखिए, WHO का कहना था कि कितने टैस्ट per million होने चाहिए - न्यूनतम 140, पर हमारे यहां इस समय 740 per million के आस-पास टैस्टस हो रहे हैं। पहले जो एक बात थी कि टैस्टिंग नहीं हो रही है, तो अब टैस्टिंग प्रचुर मात्रा में हो रही है, क्योंकि ज्यों-ज्यों संसाधन बढ़ते चले गए, संसाधनों के विस्तार के साथ सरकार ने टैस्टिंग को भी आगे उसी हिसाब से बढ़ाने का प्रयास किया। इन कुछ महीनों में 13,14,646 आइसोलेशन बेडज़ बने, 2,31,093 ऑक्सीज़न से युक्त बेडज़ बने, 62,000 से अधिक आईसीयू बेड्ज़ बने, जिनमें 32,575 वेंटिलेटर युक्त बेड्ज़ थे। उल्लेखनीय बात यह है कि जब यह क्राइसिस शुरू हुआ, तब हमारे यहां वेंटिलेटर नहीं बनते थे। अब वेंटिलेटर बन भी रहे हैं और उनको बाहर भी भेज रहे हैं। अगर हम कूल मिलाकर देखें तो इस समय देश में 15,284 कोविड सेंटर्स हैं और 12,826 आइसोलेशन सेन्टर्स हैं। यानी इन महीनों में संसाधनों की अभिवृद्धि जितनी की जा सकती थी, उसे हमने करने का पूरा प्रयास किया है और इसी दिल्ली में 10 हजार की क्षमता वाला एक कोविड हॉस्पिटल है, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री, श्री अमित शाह जी ने किया था। भारतीय केंद्रीय रिज़र्व पुलिस फोर्स ने उसे खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। अब जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया था कि तीन वैक्सीन्स के ऊपर एडवांस्ड स्टेज में काम चल रहा है और अभी समाचार पत्रों में आया था कि शायद रूस से वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया भी आगे चल रही है। ये वे चीजें हैं. जहां

हम संसाधनों के विकास में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ हमने नयी प्रक्रियाओं का भी प्रयास किया। क्यों हम एक ही प्रकार की चिकित्सा पद्धति से ही इसका समाधान पाने का प्रयास करें, इसलिए Interdisciplinary Ayush Research and Development Taskforce का गठन किया गया। पहली बार आयुर्वेद और CSIR मिलकर रिसर्च करेंगे क्योंकि general immunity को बढ़ाने की जो क्षमता आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में है, वह सामान्यवार चिकित्सा पद्धतियों में नहीं थी। इसलिए इसका भी एक प्रयास किया गया और पहली बार ऐसा हो रहा है, जब उन गैर परम्परागत चीज़ों को - जिन्हें mainstream से हटकर गैर-परम्परागत चिकित्सा माना जाता था - mainstream में लाकर वैज्ञानिकता के साथ स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी vaccine भी और immunity बढ़ाने का प्रयास भी - यह एक alternative technology से आगे बढ़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने संसाधनों में आगे बढ़ने का कितना कार्य किया। अभी हमारे एक सम्मानित सदस्य उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न कर रहे थे तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में लगभग ब्राज़ील के बराबर है। आज अगर आप तुलना करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23.78 करोड़ है और ब्राजील की जनसंख्या 21 करोड़ है, लेकिन ब्राजील में 34.6 लाख केसेज़ हैं और उत्तर प्रदेश में 1.11 लाख केसेज़ हैं। जहां तक death का सवाल है तो ब्राज़ील में 1.72 लाख लोगों की मीतें हुई हैं और उत्तर प्रदेश में 2,867, जबिक testing उत्तर प्रदेश में इस समय सर्वाधिक हो रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश तो छोड़िए, जो लोग उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न कर रहे थे - चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने की दिशा में इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है कि अगर हम ब्राज़ील के infrastructure से उसकी तूलना करें तो वह काफी बड़ी उपलब्धि नज़र आती है ।

उपसभापित महोदय, अगला विषय यह आता है कि सिर्फ संसाधन ही नहीं, संवेदनशीलता भी चाहिए। यदि संवेदनशीलता की बात आती है तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने जब यह घोषणा की कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा - और अब तो यह कर दिया कि नवम्बर के महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा, तो मैं यह नहीं कह रहा कि यह कोई बहुत बड़ी बात उनके लिए की है, लेकिन यह सिर्फ संवेदनशीलता का प्रमाण है। जिस समय हमने कहा कि middle class के लिए EMI में छूट हो या MSME के लिए परिभाषा में ही बदलाव कर दिया गया तो यह सिर्फ संवेदनशीलता का ही कमाल था। इतना ही नहीं, लोगों को सीधे उनके खाते में धन भी दिया गया और अनाज भी दिया गया। जो हमारे सम्मानित विरोधी पक्ष के मित्र यहां कहते हैं कि उस समय सारा पैसा कैश में देना चाहिए था तो आप बताइए, जब पहले दो महीने सम्पूर्ण लॉकडाउन था, उस समय अगर किसी के पास पूरा का पूरा केश भी हो, तो उसके लिए भोजन जुटाना ज्यादा समस्या है - बजाय इसके कि उसके पास अनाज भी हो, "उज्ज्वला स्कीम" के तहत फी गैस भी उपलब्ध हो और कुछ पैसे भी उपलब्ध हों तो वह ज्यादा अच्छी तरह से जीवनयापन कर सकता था, जिसके बारे में सुव्यवस्थित ढंग से प्रधान मंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ काम किया है।

[डा. सुधांशु त्रिवेदी]

सर, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के मित्र अकसर शायद यह बात भूल जाते हैं कि वे सिर्फ विपक्ष में ही नहीं हैं, वे अनेक राज्यों में सत्ता पक्ष में भी हैं। अगर आप सब लोग ध्यान दें तो उत्तर भारत में सबसे समृद्ध राज्य कौन-सा माना जाता है - पंजाब; पश्चिमी भारत में देखिए तो जहां आर्थिक राजधानी है - महाराष्ट्र; पूर्वी भारत में सबसे बड़ा और सबसे सक्षम राज्य कौन-सा है - बंगाल और वह राज्य, जहां की स्वास्थ्य सेवाएं और मूल रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता सबसे ज्यादा अच्छी है, वह है - केरल, जहां के स्वास्थ्यकर्मियों की देश में ही नहीं, दुनिया में मांग रहती है तो बेहतर यह होता कि वे इन राज्यों में, जिनके पास वैसे भी अच्छे साधन हैं, कुछ करके दिखाते और फिर हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत कर देते। ...(व्यवधान)... क्योंकि हेल्थ एक प्राइमरी स्टेट सब्जेक्ट है, अपने संसाधनों से वे करके दिखाते और फिर कहते कि हमने यह किया। आप हमारे सामने उदाहरण पेश करते। ...(व्यवधान)... यह होता रहा, ...(व्यवधान)... लेकिन आप याद करिए, जिस समय कोविड के दौर में राहुल गांधी जी तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी जी से भी बात की थी - आपमें से कोई भी जाकर चेक कर सकता है। जब मज़दूरों का विषय आया और वह मुम्बई के संदर्भ में था तो अभिजीत बनर्जी जी का विचार था, यह कोई हमारा विचार नहीं है कि मज़दूरों की समस्या मूलत: स्थानीय सरकारों की समस्या है और उन लोगों को इसे अधिक सक्रियता से लेना चाहिए, केन्द्र सरकार इसमें सिर्फ सहयोग कर सकती है। महोदय, केन्द्र सरकार ने अपनी तरफ से इसमें जो सहयोग करने का प्रयास किया, उसमें चाहे ट्रेंस के माध्यम से लाखों मज़दूरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाना हो अथवा "वन्दे भारत मिशन" के द्वारा विदेश में फंसे हुए भारतीयों को लाना हो - इस प्रकार के सभी कार्य संवेदनशीलता के साथ हमारी सरकार ने इस दरमियान किए। सर, वैसे विपक्ष की सरकारों ने भी उस समय कुछ अच्छे कामों की न्यूज़ बनाई थी। उपसभापति महोदय, याद करिए, जब कोविड का प्रारम्भिक दौर था, तब लोग भीलवाड़ा मॉडल की बात करते थे। फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वह भीलवाड़ा मॉडल चलाने वाली सरकार खाली बसों को भगाने में और भागते विधायकों को बचाने के बीच के गडबडझाले में फंस गई और वह भीलवाडा मॉडल पीछे रह गया। ...(व्यवधान)... मैंने कहा है कि संकल्प भी चाहिए था, समन्वय भी चाहिए था, संवेदनशीलता भी चाहिए थी और संसाधन भी चाहिए थे। ...(व्यवधान)... यह सब हम लोगों ने किया, परन्तु मैं एक बात यह कहना चाहुंगा। ...(व्यवधान)... देखिए, एक विकराल समस्या जब सामने नज़र आती है, जिसका कि कोई सहज, सामान्य समाधान नज़र नहीं आ रहा हो, तो उसको देखकर अक्सर बड़े-बड़े लोगों की बुद्धि विकल हो जाती है। जहां अनुमान और अटकल से लेकर समाधान निकालना हो, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कोई प्रोसीज़र नहीं होता है, तो ऐसे समय में आत्मबल से युक्त जो नेतृत्व है, वह बुरे दौर में कैसे देश का नेतृत्व करता है, उसका प्रमाण होता है और आज हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का जन्म दिन भी है, तो मैं स्मरण करता हूं कि उन्होंने जिस दृढ़ता का परिचय दिया ...(व्यवधान)... इस समय में, इस विचित्र परिस्थित में, जिसका कि समाधान तो छोडिए, जिसका स्वरूप भी किसी

के सामने स्पष्ट नहीं था। मैं यह पंक्ति उनके लिए कहता हूं कि यह संसार मनुज के लिए एक परीक्षा स्थल है।

> "दु:ख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है। किंतु स्वात्मबलविज्ञ सत्पुरुष....."

आत्मबल से विज्ञ सत्पुरुष, जैसे मोदी जी,

"किंतु स्वात्मबलविज्ञ सत्पुरुष सही पहुंच अटकल से। हल करते हैं प्रश्न सहज ही अविरल मेधाबल से।।"

और अंत में, मैं कहूंगा कि आरोप-प्रत्यारोप, आक्षेप ये सब चलते रहेंगे। मैंने अपनी बात दीये से शुरू की थी और दीये पर ही समाप्त करूंगा। अभी इसके साथ पूरा संघर्ष बाकी है।

श्री उपसभापति: डा. सुधांशु त्रिवेदी जी, प्लीज़ आप कन्क्लूड करिए।

डा. सुधांशु त्रिवेदी: सर, मैं अपनी बात अटल जी की एक पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा,

"आहुति बाकी, यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीचि हिंड्डयां गलाएं, आओ मिलकर दीया जलाएं।"

श्री उपसभापति: धन्यवाद। माननीय एल.ओ.पी.।

श्री प्रसन्न आचार्य (ओडिशा): सर, मेरी पार्टी के एक सदस्य ने भी बोलना है।

श्री उपसभापति: समय नहीं है। मेरा माननीय वक्ताओं से आग्रह है कि अगर वे अपने समय में से कुछ समय दे सकें, तो बाकी हमारे पास, जो कल से नाम आए हुए हैं, उन सबको हम समय दे सकते हैं। तीन-चार पार्टियां ऐसी हैं, जिनका बोलने का समय खत्म हो चुका है। कृपया अगर आप accommodate करेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें अच्छा लगेगा।

नेता विपक्ष (श्री गुलाम नबी आज़ाद): माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, मेरे पास बोलने के लिए आउ से दस मिनट का समय बचा है। उसमें से तकरीबन नौ मिनट मैं सुझाव दूंगा, क्योंकि यहां पर बहुत कम सुझाव आए हैं। लेकिन उससे पहले यह जरूर बताना चाहूंगा कि medical terminology में golden hours में patient को बचाने का एक प्रयास होता है। जहां तक कोविड का संबंध है, इस सरकार ने कोविड को रोकने के लिए golden months बरबाद किए। सबसे पहले December last year में World Health Organisation ने warning दी थी और उन्होंने कहा था कि चाइना-हिन्दुस्तान के नेबरहुड में एक mysterious pneumonia फैल रहा है। चूंकि

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

सबसे पहले ऐसा हमारे नेबरहुड में हो रहा था, तो हमको चौकन्ना होना चाहिए था। यह भी सच है कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इस देश को और इस सरकार को जगाने का प्रयास किया था। कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जनवरी के महीने में कहा था कि एक सुनामी आने वाली है। उसके बाद मार्च में उन्होंने कहा कि देश में एक ऐसी महामारी आ रही है, जिसकी देश कल्पना भी नहीं कर सकता है। देश को जागना चाहिए। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि वे बोले नहीं यहाँ या उस सदन में, लेकिन न बोलने की परंपरा बहुत बड़े- बड़े लोगों की भी रही है, जो न इस सदन में बोलते हैं और न उस सदन में बोलते हैं, जो परंपराएं बड़े सालों के बाद तोड़ी गई हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं।

सर, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, तब मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की बहुत सारी convocations attend की थीं। मैंने उन्हें कभी भी डॉक्टर कहकर एड्रेस नहीं किया, उन्हें हमेशा Dear Angels कहा। Angel का मतलब फरिश्ता होता है। मैं आज उन फरिश्तों को, उन angels को सलाम करता हूं, जिन्होंने कोविड बीमारी के दरमियान काम करने में अपनी जान खो दी और कुछ तो आज भी कोविड बीमारी का शिकार हुए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वे जल्दी ठीक हो जाएं और हमारे जो अन्य देशवासी हैं, जो बीमार हैं, वे भी ठीक हो जाएं।

महोदय, मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ सुझाव दूंगा। मैं समझता हूं कि बहुत टोका-टोकी हो गई है, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। यह सब जानते हैं कि किस वक्त लॉकडाउन होना चाहिए था, किस वक्त नहीं होना चाहिए था, उस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन मैं अब इसके सुधार के लिए suggestions दूंगा।

اقائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد): مانئے ڈپٹی چیئرمین سر، میرے پاس بولنے کے لئے آٹھہ سے دس منٹ کا وقت بچا ہے۔ اس میں سے تقریبا نو منٹ میں سجھاؤ دوں گا، کیوں کہ یہا ں پر بہت کم سجھاؤ آئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہوں گا، کہ میڈیکل ٹرمنولوجی میں golden hours میں مریض کو بچانے کا ایک پریاس ہوتا ہے۔ جہاں تک کووڈ کا سمبندھہ ہے، اس سرکار نے کووڈ کو روکنے کے لئے golden برباد کئے۔ سب سے پہلے پچھلے سال دسمبر میں ورلڈ ہیلتھہ آرگنائزیشن نے months

<sup>†</sup>Transliteration in Urdu script.

وارننگ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ چانناجندوستان کے نیبربڈ میں mysterious pneumonia پھیل رہا ہے۔ چونکہ سب سے پہلے ایسا ہمارے نیبرہڈ میں ہو رہا تھا، تو ہم کو چوکنا ہونا چاہئے تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ سب سے پہلے کانگریس پارٹی نے اس دیش کو اور اس سرکار کو جگانے کا پریاس کیا تھا۔ کانگریس پارٹی کے سابق ادھیکش شری راہل گاندھی جی نے جنوری کے مہینے میں کہا تھا کہ ایک سنامی آنے والی ہے۔ اس کے بعد مارچ میں انہوں نے کہا کہ دیش میں ایک ایسی مہاماری آ رہی ہے، جس کی دیش کلینا بھی نہیں کر سکتا ہے۔

[17 September, 2020]

دیش کو جگانا چاہیئے۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ وہ بولے نہیں یہاں یا اس سدن میں، لیکن نہ بولنے کی پرمپرا بہت بڑے بڑے لوگوں کی بھی رہی ہوتی ہے، جو نہ سدن میں بولتے ہیں اور نہ اس سدن میں بولتے ہیں، جو برمیرائیں بڑے سالوں کے بعد توڑی گئی ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔

سر، جب میں وزیرصحت تھا، تب میں نے گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپیٹل کے ڈاکٹرس کی بہت ساری convocations attend کی تھیں۔ میں نے انہیں کبھی بھی ڈاکٹر کہہ کر ایڈریس نہیں کیا، انہیں ہمیشہ Dear Angels کہا۔Angels کا مطلب فرشتہ ہوتا ہے۔ میں آج ان فرشتوں کو، ان Angels کو سلام کرتا ہوں، جنہوں نے کووڈ بیماری کے درمیان کام کرنے میں اپنی جان کھو دی اور کچھ تو آج بھی کووڈ بیماری کا شکار ہوئے ہیں۔ میں الله سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جادی ٹھیک ہوجائیں اور ہمارے جو دوسرے دیش واسی ہیں، جو بیمار ہیں، وہ بھی ٹھیک ہوجائیں۔

مبودے، میں یہاں پر صرف کچھ سجھاؤ دونگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ٹوکا ٹوکی ہوگئی، اس سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ کس وقت لاک ڈاؤن ہونا چاہیئے تھا، کس وقت نہیں ہونا چاہیئے تھا، اس پر بھی چرچہ ہوئی ہے، لیکن میں اب اس سدھار کے لیے suggestions دونگا۔ [श्री गुलाम नबी आज़ाद]

Sir, the sector-wise broad suggestions for the consideration of the Government are as follows:

There should be dedicated Infectious Disease Hospitals and Fever Clinics rather than calling them Covid-19 hospitals, to avoid stigma. उनको कोविड नहीं बताना चाहिए, बल्कि أن كو يہ كووڈ نہيں بنانا چاہيئے، بلكہ Dedicated Infectious Disease Hospitals and Fever Clinics कहें।

सर, मेरा दूसरा सुझाव है कि مر اسجهاؤ ہے کہ the words 'social distancing' should be done away with and we should start using the term 'physical distancing'. We need to take urgent steps to enhance our research and public health capacities. We established level BSL-4 lab in 2009 and till date, even after eleven years, there is no addition of any BSL-4 lab. The Government should immediately establish four more regional BSL-4 labs. The Government should also establish BSL-3 labs in each Medical College of the country. As each lab does not cost more than three crore of rupees, it is easy to establish them. The Government should also establish Centre for Disease Control and Health Centre of Diagnostics Facilities at the District and community centre level. While coordinated response is important, we also need to think of short-term, medium-term and long-term preparedness plans in consultation with the State Governments.

A financing strategy is needed exclusively for covering the health sector. For the Preparedness-related capacities, we need the State and District level Emergency Operation Centres and Emergency Management teams.

Now, I would like to come to the last and detailed point regarding the vaccine. It is the most important thing which our country, and, as a matter of fact, the entire world is looking forward to. It is not that the vaccine will come like any other vaccine. So, I have a number of suggestions on the vaccine because we successfully developed our domestic vaccine in 2010 and I was fortunate to have the first shot of H1N1 vaccine.

Sir, we all are aware that several candidates are in advanced clinical trials phase II and III and the vaccine will be introduced sometime in the near future. It may take three to four months or six to eight months but a vaccine will come sooner or later. Vaccine developed anywhere in the world would be in very high demand, and, therefore,

<sup>†</sup>Transliteration in Urdu script.

we must encourage domestic manufacturers and also closely follow vaccine development globally.

We should be well placed to get the vaccine at an affordable price and at an early stage through mechanisms such as prior market commitment and pooled procurement for Centre and States together. Several nations are already in talks with front runners and are securing favourable commitments for providing vaccines to their population. Timely engagement in discussions with the manufacturers as well as bilateral dialogues with the countries, those who are producing the vaccine, is required. At the same time, we must be ready for the last mile delivery of vaccine. It should not happen like this lockdown. We should be doing our preparations right now. We should plan as to how to deliver it to the last mile. We cannot afford to lose time in preparing our vaccination strategy after the procurement of vaccine. Development and finalisation of preparedness plans for the deployment of future COVID-19 vaccine is crucially important at this stage. For instance, prioritisation of target population groups-healthcare workers, elderly and the vulnerable, that is, those with co-morbidities, security personnel, those involved in travel and logistics, etc.-needs to be done. Mechanisms or platforms for delivery of vaccine at the grassroots level have to be prepared. Health system requirements— Medical Stores Organisation warehouses, cold storage and cold chain logistics for last mile transportation, identification and training of vaccinators, etc.-have to be taken care of. Regulatory pathway requirements-required safety and protocol approvalshave to be taken care of. Vaccine safety monitoring mechanisms, especially adverse events after immunisation should be looked into. In any such new vaccine, there is an adverse effect also. So, that is the most important aspect which we have to look into. Then the communication strategies-continuing with awareness and precautionary messages to avoid a false sense of safety depending on vaccine efficacy-should be strengthened. Monitoring and evaluation has to be done concurrently so that we are able to swiftly adjust and change course, as required.

Sir, in view of the fact that COVID-19 vaccine would be a new vaccine and there is a global race for developing it within the shortest time-frame possible, there could be adverse effects or side-effects or even long-term after effects which may need time to be identified, not being appropriately discovered in Phase I, Phase II or Phase III clinical trials. You may skip some adverse effects because you are doing it very quickly. Whatever time is prescribed for Phase I, Phase II or Phase III, you may cut a few months. So, there may be some lacunae left. India has to be more cautious than all other countries since we have a very large and young population. If it has an adverse effect of ten years,

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

it may be good for the countries with elderly population. But ours is a young population. So, since we have a large and young population, the Government should be overcautious and should rigorously monitor the quality, safety and efficacy of the vaccine.

My last suggestion would be that the Government, as a matter of fact, everybody, every doctor across the globe is suggesting one thing.

यह बात में हिन्दी में कहूंगा। चूंकि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में डॉक्टर्स और गवर्नमेंट्स, दिन में कई दफा हाथ धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल और सेनेटाइज़र का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं। इससे साबुन का प्रोडक्शन, खास तौर पर लाइफबॉय साबुन का प्रोडक्शन कई हजार गुना बढ़ गया है। सब इसे इस्तेमाल करते हैं और दिन में दो दफा के बजाय बीस दफा हाथ धोते हैं। इसी तरह से सेनेटाइज़र का प्रोडक्शन भी कई हजार गुना बढ़ा है। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है कि उनका मुनाफा भी कई हजार गुना हो गया है, इसलिए गवर्नमेंट से मेरी यह रिक्वेस्ट है कि साबुन की कीमत, particularly Lifebuoy साबुन, जो गरीब आदमी का साबुन है, उसकी कीमत आधी करनी चाहिए। साथ ही सेनेटाइज़र की कीमत भी आधी करनी चाहिए, तािक हर आदमी तक ये चीज़ें आसानी से पहुंच सकें। इसके साथ-साथ ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। यही मेरे सुझाव हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

أجذاب غلام نبی آزاد (جاری): یہ بات میں ہندی میں کہوں گا۔ چونکہ پوری دنیا میں، پوری دنیا میں ڈاکٹرس اور گوورنمینٹس، دن میں کئی دفعہ ہاتھہ دھونے کے لئے صابن کا استعمال اور سینیٹانزر کا استعمال کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں۔ اس سے صابن کا پروٹکشن، خاص طور پر لانف بوئے صابن کا پروٹکشن کئی ہزار گنا بڑھہ گیا ہے۔ سب اسے استعمال کرتے ہیں اور دن میں دو دفعہ کی بجائے بیس دفعہ ہاتھہ دھوتے ہیں۔ اسی طرح سے سینیٹائزر کا پروٹکشن بھی کئی ہزار گنا بڑھا ہے۔ پروٹکشن بڑھنے کا مطلب ہے کہ ان کا منافع بھی کئی ہزار گنا ہو گیا ہے، اس لئے گوورنمینٹ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ صابن کی قیمت، خاص طور پر لائف بوئے صابن، جو غریب آدمی کا صابن ہے، اس کی قیمت آدھی کرنی چاہئے۔ ساتھہ ہی سینیٹائزر کی قیمت بھی آدھی کرنی چاہئے۔ ساتھہ ہی سینیٹائزر کی قیمت بھی آدھی کرنی جاہئے۔ ساتھہ ہی سینیٹائزر کی قیمت بھی آدھی کرنی جاہئے۔ ساتھہ ہی سینیٹائزر کی قیمت بھی آدھی کرنی جاہئے، تاکہ ہر آدمی تک یہ چیزیں آسانی سے پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھہ ساتھہ آکسیجن آسانی سے میسر ہونا چاہئے۔ یہی میرے سجھاؤ ہیں، بہت بہت دھنیواد۔

(ختم شد)

<sup>†</sup>Transliteration in Urdu script.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, first of all, I want to convey my gratitude to our hon. Health Minister who made a *suo motu* statement on COVID pandemic in the House on the 15th. We have assembled here because it is our responsibility to discuss it and create confidence among the people that we are for eliminating COVID soon. That way we have to serve the people.

[17 September, 2020]

Sir, to begin with, we have to be very grateful and proud and convey our gratitude to the brave frontline warriors of battle against COVID-19. It is very heartening to see the enormous selfless efforts of our doctors, nurses, paramedical workers, lab technicians, hospital support service staff, revenue department people, Home Ministry people, innumerable volunteers and NGOs who have risen to the occasion and dedicated themselves like the brave and valiant soldiers in the field. We have to salute them.

Sir, the world does not know a single economy in the history that has been fully shut down and restarted. We are dealing with a problem of unprecedented proportions. Meeting the challenges of pandemic requires huge stimulus and better coordination between the States and the Central Government, because the State Governments are more connected with the people. The Central Government makes the policy but its implementation is done by the State Governments, Our hon, Chief Minister, when he had a video conference with our hon. Prime Minister on 11.08.2020, said, "Tamil Nadu provides effective medical treatment due to which the State has maintained a low death rate which is now at 1.6 per cent which is one of the lowest in the country." As on date, 2,44,670 patients have recovered. I am telling this to show how the State Government of Tamil Nadu is making all the efforts in conducting many tests, giving more importance to it and allocating more money to it. Till now, in Tamil Nadu, we have spent ₹ 14,878 crore for COVID control measures. In that, 50 per cent Central Government share is also there. I am not denying that. But the State Government has its own limitations in raising funds. Under the SDRF, Tamil Nadu spent ₹1,864.66 crore, but the Central Government spent only ₹510 crore. I am telling this to show how the State Government is suffering. That is why we are requesting the Central Government to come forward. Our Chief Minister reiterated this while making request to the hon. Prime Minister. We have received only ₹512.64 crore from the Government of India in two tranches under the Emergency Response and Health System Preparedness Package out of an envelope of ₹712.64 crore allotted to Tamil Nadu. He also requested that package for Tamil Nadu may be stepped upto ₹3,000 crore as per early request made by him. Both the Central and

[Dr. M. Thambidurai]

State revenues will fall short of Budget Estimates. To make up the shortfall, Tamil Nadu may be allocated ₹9,000 crore as a special grant to combat Covid and its after effects to the economy.

Sir, most of the Members also raised the point about GST. We want whatever is the highest to be given to the States. But the Finance Minister has a different opinion. Due to fund constraints, she may not be in a position to release all these funds. But, Sir, through you, I convey it to the Minister. This is a very important thing that your Ministry has to come forward and give arrears of GST to the State Governments. Then only, it will help us. As we have already exhausted the State Disaster Response and Mitigation Fund, our Chief Minister requested for an ad hoc grant of ₹1,000 crore from NDRF immediately to fight the pandemic. Then, releasing pending CMR subsidy of ₹1,321 crore at this time will facilitate paddy procurement. I am concerned and even our Chairman also said in his speech that farmers are fighting this pandemic and in spite of that, the production has increased. Therefore, it is high time to support the farmers. In spite of Covid, they are working very hard and producing more. Therefore, I request that whatever amount has to be given may be released. Our Chief Minister requested the Prime Minister to instruct SIDBI to provide at least ₹1,000 crore as refinance facility to Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Limited from the RBI special package. This will help revive the MSME industries in Tamil Nadu. Sir, why am I mentioning all these things?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Thambidurai, please conclude.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I have started just now but you are asking me to conclude. Covid has not concluded; Covid is here. If you are finishing off Covid, I am ready to conclude.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You always abide by time. We have paucity of time. You know better than me. You have the experience of conducting the House. Please conclude now.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I am appreciating that the Central Government is also making efforts to do that. At the same time, State Governments are very close to the public.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

DR. M. THAMBIDURAI: Therefore, I request that the Central Government gives them sufficient funds to implement the programme. Then only, it will be possible because they are close to the public. Especially the Tamil Nadu Government has made so many efforts to see that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Dr. Thamidurai.

DR. M. THAMBIDURAI: Death rate is less in Tamil Nadu because the Tamil Nadu Government has made so many efforts.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, I am calling the next speaker.

DR. M. THAMBIDURAI: Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri K. R. Suresh Reddy. You have one minute left for your party.

SHRI K. R. SURESH REDDY (Telangana): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you. I am Suresh Reddy speaking from Rajya Sabha Chamber.

Sir, vaccination is the one thing which is most awaited. I remember my younger days. The whole country used to look forward to Shrimati Jaya Bachchan's movie release. Today, the whole country is looking forward to the release of the vaccine, which is so important. In this regard, I would like to seek a few clarifications from the hon. Minister. To support the Indian companies which are developing these vaccines, what are the steps you have initiated in terms of scaling up of research and for administrative clearances, If there are any bottlenecks, what is the intervention of the Government to support them? In the funding pattern, to help and support these Indian companies to come up with a vaccine, what are the initiatives taken?

Secondly, Sir, there has been a lot of confusion about the guidelines. My assumption is that most of the guidelines issued by WHO are being followed by the Government of India and given to the States. I would like to know from the hon. Minister: What is the experience of the Government with WHO? How do they rate WHO? Do you say that it is good or is there scope for improvement or can do it better? This is very important.

Sir, the final point is about Covid warriors and the frontline workers. The Government has not mentioned how it has supported them, especially the Central Government employees. Have you given them any bonuses in their salaries?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Reddyji. ...(Interruptions)...

SHRI K.R. SURESH REDDY: In Telangana, Sir, we have done that. We have given a ten per cent rise, helping almost 75,000 health workers, police personnel, municipal workers. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. I am calling another speaker. ...(Interruptions)...

SHRI K.R. SURESH REDDY: I have only some suggestions, Sir. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Rajeev Chandrasekhar. ...(Interruptions)...

SHRI K.R. SURESH REDDY: Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Shri Rajeev Chandrasekhar.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR (Karnataka): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity to participate in this debate about the pandemic.

At the outset, I would like to thank the Chairman and the hon. Speaker of the Lok Sabha for the efforts in making this Parliament Session safer for us to do our duty as parliamentarians and I thank you, Sir.

Sir, let me first draw the attention of the House and indeed all those who are watching today, through you, that the COVID-19 pandemic is an unprecedented event in the history of the world. The world has not experienced anything like this since the Spanish Flu of 1918. While there are very many senior Members in this House, I suspect, none of us have experienced or have any knowledge or memories of the Spanish Flu.

Sir, this virus originated in China of which there is no doubt. The bizarre conduct of the Chinese Government for most of 2020 confirms that. The Chinese Government response is that it originated from a wet market in Wuhan from some bats but there are other reports that contradict that. There is growing evidence that this COVID-19 virus may have been a deliberate man-made laboratory creation in one of the Chinese PLA labs, a revelation, most recently, by Dr. Li-Meng Yan, who has recently fled to the U.S.

Sir, there is no vaccine against this virus currently. So it is safe to assume that the world remains vulnerable for the coming near-term. The impact of the pandemic shock

is already playing out. Lives have been lost. There have been businesses and job losses and livelihood declines all around us. Unfortunately, it is the weakest and the most vulnerable who are bearing the brunt of the virus as panic and income losses combine to drive millions home in trying and difficult conditions.

Sir, notwithstanding the views of the wise men and women in our opposition parties, who have become experts in hindsight, the truth is that world was flying blind about this pandemic, especially, in its early stages. Even today, as the vaccine remains elusive, people remain at risk. Governments around the world, as in India, have a tough choice between protecting health and lives versus livelihoods. It is a choice that has been forced on Governments never before in the modern age and Governments, including us, are being forced to take.

I accept that the people of India are entitled to and expect a report card from their Government. Did we do enough? Did we act in time? Did we put in necessary effort? Can people restart their lives as before? What does the future hold? These are all legitimate questions for which the Opposition and the Government should unite and find answers and solutions instead of what we see today carping and petty criticism.

Sir, the pandemic was unknown to the world. Its rapid spread, its virility, lack of vaccine and cures have posed a challenge not just to India, it has brought bigger and more prosperous nations and their health care systems to the knees. So, the enormity of the challenge that our Government faced must be understood. The fact that after 75 years, our healthcare system had been under-invested and many States were incapable of handling this crisis in early March and April, must be recognized.

So, I do hope Sir that the people of India become more aware and more informed as a result of these debates notwithstanding the petty political criticism and blind sarcasm from the Opposition instead of ideas and solutions. And Mr. Derek, you know who I mean.

Sir, there was reference to chronology and I just want to briefly touch on some issues of chronology to make a very important point. The virus started in November 2019 in Wuhan. The Chinese authorities reported it to the W.H.O. only on December 31st after a full one-and-a-half months for this to have an unfettered spread. From there on it has spread. Sir, I want to make this point. Within different countries, the virus spread through the population at varying speeds depending on a range of factors such as

#### [Shri Rajeev Chandra Sekhar]

cultural and behavourial responses of the community, population density, average household size, among others. These differences have driven the nature of spreads in each country with substantial variations also depending on the responses of this country. I make this point that it is very, very difficult to compare the spread of the disease in one country to the other because of the underlying sociological and economic factors.

Sir, I want to talk broadly about two broad issues. Some criticisms have been raised. One is about the need for the lockdown and the second is about briefly to touch upon the economy. There are some that are questioning whether there should have been a lockdown, and again I refer to this wisdom of hindsight. It is a very easy quality to develop. When tackling of virulent virus like COVID-19, early interventions are crucial to stay ahead of the disease. It is important to note that in almost all countries, the ones that were successful, had this strictest intervention like Lockdowns at the early dates versus those who had just advisories. The lockdown was necessary, unambiguously necessary, to slow the spread of the disease and to create time for the Governments, both Central and State, to build up healthcare capacity, capability and increased citizen awareness. These were critical and it terms out now that this precious time when used properly has significantly expanded testing capacities in the country, lower fatality rates and increased recovery rates. My colleague, the Trinamool M.P. spoke about nuanced lockdown, as if it is a new invention in Kolkata. No lockdown anywhere in this country has been total. Even when there was a total lockdown, the economic activity of 40 to 45 per cent under the Essential Services remained intact. So, there is no such thing as total lockdown anywhere in the country. So, there is no nuance in Kolkata that does not apply anywhere in the country. I draw the attention to the critics of the lockdown to this one statement by the Congress President, Sonia Gandhi, on April 2 and I quote, "The lockdown may have been necessary but not well-planned." That is her quote. I accept that in this country, there may be people with better ideas, better brains and I am even willing to accept that some of them are in the Congress. But, I saw no evidence at all from April 2 to today of a better 'plan' even in Congress governed States like Maharashtra. So, I will, as well as people of India, take this criticism for what it iscriticism for the sake of it.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (Karnataka): Why are you going on party lines?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: No, Sir, this is not good. We all decided here to support the Government in these critical times.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. I think, we all should follow the norms. ...(Interruptions)... It is a good suggestion but we all should follow those norms. ...(Interruptions)...Please. ...(Interruptions)...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir. he should...

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Khargeji, I am responding to... ... (Interruptions)...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, this is not good.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak to the Chair, Shri Chandrasekhar.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Sir, I will end by just reminding my colleagues in the Opposition that after the lockdown was imposed, the United Nations praised India's response to the Pandemic as 'comprehensive and robust', terming the lockdown restrictions as aggressive but vital. The Oxford COVID-19 Government Response Tracker noted the Government's swift and contingent actions, emergency policy-making, emergency investment in healthcare, fiscal stimulus and investment in vaccine and R&D and gave India a score of 100 for the strict response. Sir, my colleague, Dr. Sudhanshu has already spoken about as to how the Government used this opportunity of lockdown to do an un-precedented expansion of healthcare capacity in the country; un-precedented since Independence that we have expanded our testing, vaccine capacity, and R&D capacity at this level in just 100 days. So, I will not mention that any more.

I will end by saying on this issue of lockdown that lockdown has been vindicated by the expanding testing capacities, lower fatality rates and high recovery rates. I say this with all responsibility. Lockdowns are a necessary tool in the toolkits of responsible Governments, which need to be used sparingly because of its high cost but will be around as a contingency plan as long as the vaccine remains elusive. I want to talk a little bit about the economy as there have been comments about the economy and handling of the economy.

[Shri Rajeev Chandra Sekhar]

We are in the midst of biggest economic crisis the world has ever seen. This pandemic has devastated economies around the world and global trade. Very soon after the pandemic started, 65 per cent of the global trade was impacted and the world's largest consuming and investing economies were hit hard. The Indian economy depends on manufacturing, service sector, exports and foreign investment and all of those four pillars on which the Indian economy rests were hit hard. The economic impact was wide as well as deep. And Sir, it is clear from the get-go that conventional economic thinking and theories had no solution for this type of crisis. So the priority of the Government was to ensure a soft landing of the economy and livelihood, during the inevitable contraction. Soft landing of the economy was to ensure minimum damage to the real economy. To this end, the Government moved decisively and comprehensively. It announced moratoriums on tax payments, GST payments and loans; provided indirect income support to small businesses through PF contributions; expanded the definition of MSMEs; provided liquidity support to the MSMEs, direct debit transfers and expanded MNREGA for the poor. Significant financial support from the Government was directed at the most vulnerable parts of our economy, the MSMEs and the poor. And, Sir, I want the House to recognize this. The decisions taken by our hon. Prime Minister in his first term like the JDY, direct benefit transfer, cleaning up of the financial sector have been very important and have played the role of a bulwark in this crisis. For example, our financial sector is cleaner and qualitatively in much better shape than it was ever been in 2004. It is to the credit of this Government that the financial sector rebuilds since the dark days of 2014 as has become a significant strength to the Government and the economy when liquidity in excess of ₹ 10 lack crores, the financial sector has served as the bulwark against the economic losses due to the pandemic. So it is indeed ironic when former UPA constituents of Ministers wax eloquent of our economy today because they need to be reminded and I do this respectfully, through you, again and again, about the sorry state of the economy and financial sector left behind in 2014. Sir, the increased delivery of credit to small businesses and to the Government for its increased pending on the rural and the poor and the unprecedented expansion of the healthcare by the Government and to meet deficits in tax and GST revenue was only possible because of the strength of our financial sector. The banking system has alone delivered ₹ 2 lakh crores during the lockdown an additional credit to the MSMEs during this period. Our markets have remained stable and functional, yields on long term bonds have remained

stable. The RBI has been pro-active with its Repos and LTRs to keep yields down and currency stable. That soft landing was the first step which the Government managed successfully. The next step was to reboot and restart. At this stage, a lot of Members have raised the issue of minus 23.9, and a few one, and I want to squarely take this on, Sir, because it is even ironical that my colleagues in the Left are suddenly obsessed with the GDP and the numbers that the GDP is throwing up. I think most have jumped into this eagerly thinking it is a piece of bad news that they can target the Government with. Sir, the facts are these. Every major economy in the world has taken a deep hit from April to June. Different countries had different levels of lockdown, different levels of economic activities and stimulus. Countries like the US who use printing of the US dollar as stimulus, had massive stimulus packages of trillions of dollars and a mixed lockdown. Countries like UK were minus 20 per cent for the quarter. Japan was minus eight for the quarter, annualized at minus 27.8 and Germany was minus 11.7. The point is, not to throw numbers around. These numbers are not comparable with each other because of the different nature of each economy and the different types of lockdown adopted by it. As I have mentioned earlier, the lockdown was necessary to slow the disease. India was locked down for most of April and May, and then in parts of June and July. This meant just simple mathematics for anybody who really wants to understand that 60 per cent of our economy was shut down for two months or eight weeks. Imagine that, Sir, when 60 per cent of our economy at ₹20 lakh crores of GDP per month was locked down, the impact was expected. This means that our economy could have contracted up to -40 per cent for that quarter. But, the fact that it was only -23.9 per cent was a result of the many directed packages to MSMEs and other parts of the economy from the Government. That is a good news. Now, those in the Opposition that are focusing on this number, leave out the rest of the story very conveniently. Our economy have bounced back to 85 per cent of its pre-Covid level in June itself and then remained at that level in July and most of August, despite lockdowns in Mumbai and Bengaluru in July. Post-May, the unlocking process has proceeded upwards for the economy. The economy has revived in V-shape curve from being at 40 per cent of pre-Covid levels in May to 85 per cent in June and about 90 per cent in August. The GDP for April-June quarter maybe about -6 and this quarter, about -1 to -2 per cent and Q3 and Q4 being stronger quarters as the economy builds back. I am not a predictor or an astrologer. But, we can, I believe, expect the possible overall GDP contraction for the year at a range of -6 to -10 per cent, depending on the second half of this year. The question remains. And, it is a good thing

#### [Shri Rajeev Chandra Sekhar]

for this House to be aware of this and discuss. What are the implications of this kind of economic contraction of -6 to -10 per cent? This is an important thing for us to understand. This is a one-time loss to the country similar to the ones that States suffered during a natural calamity like floods and droughts. There is no cause for it that is in our control as Government or citizens. The difference is this, when States have losses due to floods and droughts, the Centre steps in. But, this loss is for the entire country and the whole country needs to bear this. There is no one else to forward these losses to. There is nobody else. Unless, maybe China accepts their responsibility and there is a case for reparation. This needs to be understood, especially, those Opposition States that keep talking about GST shortfalls and I don't want to come to that controversy, but I will ask the Opposition Members a simple question. If there was no GST today, wouldn't their revenues as States have taken a hit in the event of the Covid-19 pandemic? There is no one to pass this bill to. The economic loss due to this pandemic is the country's loss and will have to be shared. Some colleagues have commented on the inadequacy of the ₹20 lakh crore Atmanirbhar Package. This is an important point. I will say this and then I will conclude. It is not comparable; it is not big enough compared to the US. These are some of the comments made on this. But, I would respectfully submit for the understanding of our Members. This Government's approach to this economic crisis is not to make wild, rash economic decisions to get a few headlines like what we saw in 2007-2008. The country and its citizens paid a huge price for recklessness of the 2008 on the fiscal profligacy of the then Government that broke up financial sector. The Narendra Modi Government's approach is careful, calibrated and medium-term. You may well ask why medium term! Why not do everything today? The answer is simple. As long as the vaccine is not around, the pandemic remains a clear and present danger to the economy. The only real guarantor of our economy is the strong Government with strong financial options. This needs to be understood. The Government's financial options must remain intact for as long as the pandemic remains. The Government's response has to be a continuing one and giving Government the capacity to intervene in the future also. The Government's response is being exactly right. It has been responsive. It has been calibrated. It knows it has to play the long game as the most important player of the economy. Conventional economic theories simply don't work in today's crisis. The economy has soft-landed. Economic activities are slowly and surely building up. MSMEs are being credit-supported. Non-MSME businesses are being

#### MESSAGE FROM LOK SABHA

#### The Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha.

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 16th September, 2020."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

श्री देरेक ओब्राइन (पश्चिमी बंगाल): सर. दो-दो मिनट दे दीजिए...